अवध की आवाज

www.avadhkaawaz.com

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र राजधानी लखनऊ उत्तर प्रदेश से प्रकाशित

वर्ष–12 अं क– 226 R.N.I.- UPHIN/2012/45127 लखनऊ शुक्रवार 15 दिसम्बर 2023 पृष्ठ – 4 मूल्य–3 रूपया

संक्षिप्त समाचार

मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्रीराम के पग चिन्हों पर चलना ही ममता चौरिटेबल ट्रस्ट का उद्देश्य : राजीव मिश्रा

लखनऊ। परहित सरिस ध र्म नहि भाई , पर पीड़ा नहि सम अधमायी,,कविता कानन केसरी,भक्ति शिरोमणी महात्मा तुलसी दास के इसी युक्ति से प्रेरित होकर ममता चौरिटेबल ट्रस्ट नर सेवा को नारायण सेवा मानकर रामराज की संकल्पना को फलीभूत करने में निरन्तर कार्य कर रही हैं!मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्रीराम के पग चिन्हों पर चलकर निरन्तर सेवा,समर्पण,सहयोग एवं त्याग के माध्यम से समाज की सेवा विभिन्न माध्यमों से कर रही है उक्त विचार प्रेम मूर्ति प्रेमभूषण जी ने ममता चौरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में व्यक्त किया!आध्यात्मिक चेतना एवं धार्मिक जागरण हेतु प्रत्येक वर्ष 17 दिसम्बर से 25 दिसंबर तक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त श्री राम कथा के सरस गायक परम पूज्य प्रेम मूर्ति प्रेम भूषण जी महराज के सानिध्य में नव दिवसीय श्रीराम अमृत वर्षा का आयोजन होता है उसी क्रम में इस बर्ष भी 17 दिसंबर से 25 दिसंबर तक श्रीराम कथा अमृत वर्षा का आयोजन पूज्य श्री के श्रीमुख से गोमती नगर विस्तार सीएमएस फेज 2 के बगल लखनउ में होना सुनिश्चित है!आप सभी कथा का रसपान करने केलिए सादर आमंत्रित है! उक्त बात ममता चौरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापक अध्यक्ष एवं भारतीय जनता पार्टी के अवध क्षेत्र उपाध्यक्ष राजीव मिश्रा ने एक प्रेस वार्ता में व्यक्त किया!श्री मिश्रा ने श्री राम कथा अमृत वर्षा के कार्यक्रमों की विस्तृत चर्चा करते हुए बताया कि कथा के 9 वे दिन 25 दिसंबर की कथा भारत रत्न श्रद्धेय अटल जी के नाम समर्पित होगी तथा समापन अवसर पर विशाल अटल भंडारा आयोजित होगा.22 जनवरी को प्रभु श्रीराम अपने अयोध्या जी धाम के नव निर्मित भव्य मन्दिर के गर्भ गृह में विराजमान होगे, ममता चौरिटेबल ट्रस्ट प्राण प्रतिष्ठा के पूर्व श्री राम अमृत वर्षा के आयोजन से मानवता को राममय करके अलख जगा रही है! आदरणीय मोदी जी और योगी जी के रामराज के सपने को पूरा करने में हम सबको साथ आना होगा।

राजकीय आईटीआई लखनऊ में 16 दिसम्बर को कैंपस ड्राइव का आयोजन

लखनऊ। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अलीगंज लखनऊ में हिन्दूस्तान यूनीलीवर लिमिटेड, सूमेरपुर, हमीरपुर, उत्तर प्रदेश के कैम्पस ड्राइव का आयोजन 16 दिसंबर द्वाराकिया जा रहा है। ट्रेनिंग काउंसिलिंग एण्ड प्लेसमेन्ट आफिसर एमए खाँ ने बताया कि कम्पनी में परमानेन्ट जॉब के अवसर है। जिसमें शैक्षिक योग्यता आईटीआई के फिटर, टर्नर, मशीनिष्ट, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रानिक मैकेनिक, इन्ट्रूमेन्ट मैकेनिक एवं डिप्लोमा इलेक्ट्रीकल, मैकेनिक के उत्तीर्ण किया हो वे ही प्रतिभाग कर सकते है। साथ ही 1 वर्ष का अनुभव प्राप्त किया हो या अप्रेन्टिसशिप या सीआईटीएस किया हो वे पात्र होंगे। जिसकी आयुसीमा 20 से 30 वर्ष हो। वेतन 10 हजार से 12 हजार रुपये प्रतिमाह एवं अन्य सुविधाएं कम्पनी द्वारा दी जायेगी। मेले में केवल महिला अभ्यर्थी प्रतिभाग कर सकते है। कुल 200 पदों पर चयन किया जायेगा।

अन्तर्राष्ट्रीय पर्यावरण ओलम्पियाड आईईओ-2023 का भव्य समापन

प्राइसलेस पर्ल स्कालर्स एकेडमी, नासिक, महाराष्ट्र ने जीती ओवरऑल चैम्पियनशिप

लखनऊ। सिटी मोन्टेसरी स्कूल, गोमती नगर द्वितीय कैम्पस द्वारा आयोजित चार दिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय पर्यावरण ओलम्पियाड (आई.ई.ओ.–2023) का भव्य समापन आज सायं सी.एम.एस. कानपुर रोड ऑडिटोरियम में सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर देश–विदेश के प्रतिभागी विजयी छात्रों को शील्ड, मैडल व सार्टिफिकेट प्रदान कर पुरष्कृत कर सम्मानित किया गया। 'आई.ई.ओ.–2023' की प्रतियोगिताओं में प्राइसलेस पर्ल स्कालर्स एकेडमी, नासिक, महाराष्ट्र की छात्र टीम ने ओवरऑल चैम्पियनशिप जीतकर अपने ज्ञान विज्ञान का परचम लहराया जबकि सिटी इण्टरनेशनल स्कूल, मानस सिटी, लखनऊ एवं सेठ एम आर जयपुरिया स्कूल, कुर्सी रोड, लखनऊ की छात्र टीमें रनरअप रही। विदित हो कि सी.एम.एस. गोमती नगर द्वितीय कैम्पस द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय पर्यावरण ओलम्पियाड का आयोजन 11 से 14 दिसम्बर तक सी.एम.एस. कानपुर रोड ऑडिटोरियम में किया गया, जिसमें नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, अमेरिका, रूस, यूएई, सऊदी अरब एवं भारत के विभिन्न प्रान्तों के लगभग 500 छात्रों ने प्रतिभाग किया। मुख्य अतिथि प्रशांत किशोर सिंह, डेप्युटी डायरेक्टर जनरल, यूनीक आईटेन्टीफिकेशन ऑफ इण्डिया ने दीप प्रज्वलित कर समापन समारोह का शुभारम्भ किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री सिंह ने कहा कि विश्व का बदलता पर्यावरण आज मानवता के लिए चुनौती है, ऐसे में यह आवश्यक है कि किशोर व युवा पीढी पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हो। अन्तर्राष्ट्रीय पर्यावरण

ओलम्पियाड की संयोजिका व सी.एम.एस. गोमती नगर द्वितीय कैम्पस की वरिष्ठ प्रधानाचार्या सुश्री मंजीत बत्रा ने कहा कि यह अन्तर्राष्ट्रीय पर्यावरण ओलम्पियाड युवा पीढ़ी को पर्यावरणीय सुरक्षा का अग्रदूत बनाने के अपने लक्ष्य में सफल रहा है। आई.ई.ओ.–2023 की सह–संयोजिका एवं सी.एम.एस. गोमती नगर द्वितीय कैम्पस की प्रधानाचार्या श्रीमती संगीता बनर्जी ने देश–विदेश से पधारे प्रतिभागी छात्रों व शिक्षकों का हार्दिक आभार व्यक्त किया। समापन समारोह में सी.एम.एस. छात्रों ने शिक्षात्मक–साँस्कृतिक कार्यक्रमों की सतरंगी छटा बिखेर कर देश–विदेश से पधारे छात्रों व टीम लीडरों को मंत्रमुग्ध कर दिया। सी.एम.एस. के मुख्य जन–सम्पर्क अधिकारी हरि ओम शर्मा ने बताया कि समापन समारोह से पूर्व देश–विदेश से पधारे सभी प्रतिभागी छात्र व टीम लीडर आज लखनऊ भ्रमण पर निकले और बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, रेजीडेन्सी, घंटाघर आदि ऐतिहासिक स्थलों को देखने गये। लखनऊ भ्रमण पर प्रतिभागी छात्र खासे उत्साहित व प्रफुल्लित थे। लखनऊ की गलियों में घूमते हुए इस दल ने विश्व एकता व विश्व शांति का अद्भुद दृश्य उपस्थित किया। एक अनौपचारिक वार्ता में इन छात्रों ने कहा कि लखनऊ में बहुत अपनापन मिला है और हम फिर से यहाँ आना चाहेंगे। श्री शर्मा ने कहा कि हालाँकि यह चार दिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पियाड आज सम्पन्न हो गया परन्तु इसके माध्यम सी.एम.एस. ने पर्यावरण संवर्धन की जो मशाल जलाई है, उसकी रोशनी सारे विश्व में अवश्य फैलेगी।

सीएसआईआर-एनबीआरआई, लखनऊ एवं राष्ट्रीय पर्यावरण विज्ञान अकादमी द्वारा

पर्यावरणीय मुद्दों पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मलेन का उद्घाटन

लखनऊ। सीएसआईआर–राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, लखनऊ एवं राष्ट्रीय पर्यावरण विज्ञान अकादमी (नेसा) के संयुक्त तत्वाधान में 14 से 16 दिसम्बर के मध्य ग्रीन केमिस्ट्री, प्रदूषण रोकथाम एवं जलवायु परिवर्तन पर आधुनिक प्रवृत्तियों एवं चुनौतियों पर तीन दिवसीय राष्ट्रीय सम्मलेन का

उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार के अपर मुख्य सचिव डॉ. देवेश चतुर्वेदी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। उद्घाटन सत्र में संस्थान के वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक एवं सम्मेलन के संयोजक डॉ. पंकज कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि इस राष्ट्रीय सम्मेलन में देश भर के 19 प्रदेशो के करीब 68 शहरों से 70 से जयादा शैक्षिक व अनुसंधान संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों से 200 से ज्यादा प्रतिभागी शामिल हो रहे है,पर्यावरण विज्ञान पर केन्द्रित इस सम्मेलन में मुख्य रूप से प्रदूषण एवं निस्तारणय जलवायु परिवर्तनय हरित रसायन विज्ञान, पर्यावरण और जैव प्रौद्योगिकी, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और समसामयिक मुद्दों पर वैज्ञानिक एवं विशेषज्ञों द्वारा 80 से ज्यादा मौखिक प्रस्तुतियां, 110 पोस्टर प्रस्तुतियों के द्वारा परिचर्चाए की जाएगीद्य इसके साथ ही देश के नामी विषय विशेषज्ञों द्वारा 13 मुख्य व्याख्यान प्रस्तुत किये जा रहे हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण विज्ञान अकादमी (नेसा) के कार्यकारी अध्यक्ष श्री आर के सिन्हा ने अकादमी के निर्धारित लक्ष्यों एवं हालियाँ उपलाधियों की जानकारी देते हुए बताया कि वैश्विक स्तर पर बढ़ते प्रदूषण एवं उसके दुष्प्रभावों के प्रति राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर विभिन्न कार्यक्रमोंध्संगोष्ठियों के आयोजन द्वारा हम जनमानस जागरूकता बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। इससे पूर्व सभी गणमान्य अतिथियों का स्वागत करते हुए संस्थान के निदेशक डॉ. अजित कुमार शासनी ने कहा कि इस सम्मेलन द्वारा सृजित निर्देशों एवं सुझावों के द्वारा हमे प्रदूषण एवं जलवायु परिवर्तन की नई चुनौतियों के हल खोजने में अवश्य सहायता मिलेगी। इस अवसर पर राष्ट्रीय पर्यावरण विज्ञान अकादमी, नई दिल्ली द्वारा विभिन्न वार्षिक सम्मान पुरस्कारों की भी घोषणा की गयी जिनमे मुख्य रूपसे,नेसा विशिष्ट फेलोशिप अवार्ड–डॉ. ए के सिंह, प्रोफेसर, भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, बीएचयु, वाराणसी,नेसा फेलोशिप – देश भर के विभिन्न संस्थानों से 21 विशेषज्ञों,वैज्ञानिकों को चयनित किया गया, नेसा प्रख्यात वैज्ञानिक पुरस्कार – देश भर के विभिन्न संस्थानों से 10 विशेषज्ञों,वैज्ञानिकों को चयनित किया गया, नेसा अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पुरस्कार–डॉ. सदानंद मुग्गेरी, कर्नाटक विश्वविद्यालय एवं श्री सितेंदु मंडल, सीएसआईआर –सीजीसीआरआई, कोलकाता नेसा हरित प्रौद्योगिकी अवार्ड–डॉ. डी नरेन्द्र कुमार, नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ ओसियन टेक्नोलॉजी, चेन्नई एवं डॉ. सुमन पुरोहित, नैनीताल उत्तराखंड काउंसिल फॉर बायोटेक्नोलॉजी नेसा विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार – देश भर के विभिन्न संस्थानों से 8 विशेषज्ञों,वैज्ञानिकों को चयनित किया गया।नेसा श्रीमती कनक सिन्हा स्मृति अवार्ड–डॉ. रचना सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, एमिटी यूनिवर्सिटी, लखनऊ उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि डॉ. देवेश चतुर्वेदी ने अकादमी द्वारा सम्मानित सभी वैज्ञानिकों,शोधार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि हम विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों और जलवायु परिवर्तन के मुद्दों से निपटने के लिए बेहतर तकनीकी विकास और उनकी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, उन्हें देखते हुए इस सम्मेलन का विषय बहुत प्रासंगिक है। डॉ.चतुर्वेदी ने इस बात पर जोर दिया कि अनुसंधान संस्थानों और विश्वविद्यालय द्वारा इस सम्मेलन की सिफारिशों और कार्यवाही को हितधारकों तक अवश्य पहुचाना चाहिए ताकि इन मुद्दों से निपटने के लिए उचित नीतियां समय पर बनाई जा सकें। हाल के पर्यावरणीय मुद्दों पर चर्चा करते हुए डॉ.चतुर्वेदी ने कहा कि हमें अपनी मानवता को प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के खतरनाक परिणामों से बचाने के लिए हरसंभव प्रयास करने होंगे। सम्मेलन में आज मुख्य व्याख्यानों में कलिंगा इंस्टिट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, भुबनेश्वर की डॉ. संजुक्ता साहू ने एनर्जी एफीसियेंट बिल्डिंग टुवर्ड्स क्लाइमेट चेंज मिटीगेशन परय लखनऊ यूनिवर्सिटी की डॉ पूर्णिमा वाजपेयी ने रिस्क इम्पोस्ड बाई मैटेलिक नैनोपार्टिकल दू मेडिसिनल प्लांट्स इन एग्री–एनवायरनमेंट परय नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ ओसियन टेक्नोलॉजी, चेन्नई के डॉ. डी राजशेखर ने इन्नोवेटिंग फॉर ग्रीन फ्यूचर पर तथा यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, चेन्नई के डॉ. एम सुरेश गाँधी ने एप्लीकेशन ऑफ फॉरअमिनीफेरा फॉर इकोलॉजी एंड पोलूशन मोनिटरिंग स्टडीज पर अपने अपने मुख्य व्याख्यान प्रस्तुत किये। सम्मेलन फ्लोरा फौना साइंस फाउंडेशन द्वारा आयोजित एक विशेष सत्र में संस्थान के निदेशक डॉ. अजित कुमार शासनी द्वारा तीसरा प्रो. सुशील कुमार स्मृति व्याख्यान प्रस्तुत किया गया। इस सत्र में फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष एवं पूर्व निदेशक, सीएसआईआर –सीमैप, लखनऊ डॉ. एस पी एस खनुजा भी उपस्थित रहे। आज सम्मेलन में प्रतिभागियों द्वारा कुल 28 मौखिक व्याख्यानों एक साथ साथ 28 पोस्टर प्रस्तुतियों को प्रस्तुत किया गया।

17 करोड़ से बना किसान बाजार,8 महीने से धूल फांक रहा, 42 दुकानों का होना है आवंटन

बहराइच। जिले में अपनी फसल बेचने के लिए दूर न जाना पड़े। इसके लिए योगी सरकार जिलों में किसान बाजार बना रही है। लेकिन कुछ अफसरों कि वजह से ऐसा नहीं हो पा रहा है। इसका ताजा उदाहरण है बहराइच में पिछले 7 साल से बन रहा किसान बाजार। यह बाजार बनकर तैयार तो है, लेकिन आज भी वीरान पड़ा है। इस वीरान पड़े किसान बाजार 2 साल में पूरा होना था। किसान बाजार को बनने में 6 साल क्यों लगे? साल 2015 में बहराइच की मंडी समिति ने बड़े जोर–शोर से मंडी परिषद, लखनऊ को प्रस्ताव दिया कि हमारे यहां के किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए काफी दूर जाना पड़ता है। इसलिए हम चाहते हैं कि उनके लिए बहराइच में ही किसान बाजार बना दिया जाए। लखनऊ मुख्यालय ने भी इस प्रस्ताव को हाथों हाथ लिया। किसान बाजार बनाने कि हरी झंडी दे दी। जगह का सिलेक्शन हो गया और जनवरी, 2016 में प्रस्ताव भी पास हो गया। तय हुआ कि 2 साल में किसान बाजार बनकर तैयार कर लिया जाएगा। इसके बाद मंडी परिषद की निर्माण और विदयुत खंड इकाई सक्रिय हो गई। टेंडर जारी कर काम भी शुरू करा दिया गया। मगर इसके बाद ही अफसरों का खेल भी शुरू हो गया। कहा जाने लगा कि किसान बाजार बनाने की जगह सही नहीं है। इसके बाद प्रोजेक्ट को भी रोक दिया गया। लेकिन बाद में सिर्फ बेसमेंट बनाने और लागत 17 करोड़ करने की शर्त पर प्रोजेक्ट फिर से शुरू हुआ। काफी अडचनों के चलते 2 साल में पूरा होने वाल प्रोजेक्ट 6 साल में यानी 2022 में पूरा हो पाया। सिर्फ बेसमेंट में बनकर तैयार हुए किसान बाजार में कुल 42 दुकानें हैं। साथ ही 50 कारों का पार्किंग एरिया भी बनाया गया है। कंस्ट्रक्शन का काम पूरा होने के साथ ही विद्युतीकरण का काम भी पूरा हो चुका है। 11 झट की लाइन और इसके निरीक्षण के लिए 39 लाख रुपए विद्युत विभाग में जमा किए जा चुके हैं। पिछले करीब 8 महीने से परिसर में लगे बिजली के इन उपकरणों की रखवाली एक व्यक्ति कर रहा है। जिस पर महीने का खर्च 15 हजार सैलरी और अन्य खर्चों के साथ मिलाकर करीब 20 हजार है।

दरअसल, किसान बाजार में कुल 42 दुकानें बनी हैं। एक दुकान की कीमत 30 लाख रखी गई है। ये दुकानें व्यापारियों को बेची जाएंगी, जो किसानों से उनकी उपज खरीदेंगे। इससे किसानों को बहराइच से बाहर नहीं जाना पड़ेगा और ट्रांसपोर्ट पर कम खर्च के चलते उनकी आमदनी बढ़ जाएगी। इस बारे में जब गहनता से पड़ताल की गई।

बहराइच मंडी परिषद के सचिव धनंजय सिंह इन दुकानों के आवंटन में रोड़ा बने हुए हैं। वह निर्माण खंडों (सिविल और विद्युत) से हस्तांतरण ही नहीं ले रहे हैं। इसके पीछे भी एक कहानी है। दरअसल, जिस समय किसान बाजार बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई, उस समय धनंजय सिंह सचिव नहीं थे। वह अभी कुछ समय पहले ही सचिव बनाए गए हैं। इसके चलते वह दुकान आवंटन की प्रक्रिया में रोड़ा हैं। डीएम मोनिका रानी ने बताया कि इस प्रकरण की जानकारी नहीं थी। अब प्रकरण संज्ञान में आया है। नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। किसान राजितराम ने बताया कि किसान बाजार बनने से सके उम्मीद जगी हुई थी। लेकिन वह सफेद हाथी साबित हो रही है। किसान बाजार शुरू होने से काफी राहत मिलेगा।

'ऑल इण्डिया लॉ इन्ट्रेन्स टेस्ट' में सीएमएस की कनिष्का मित्तल 'सिटी टॉपर'

सर्वाधिक 13 छात्र सी.एम.एस. से चयनित

लखनऊ। सिटी मोन्टेसरी स्कूल की मेधावी छात्रा कनिष्का मित्तल ने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, दिल्ली के तत्वावधान में आयोजित 'ऑल इण्डिया लॉ इन्ट्रेन्स टेस्ट (एआईएलईटी)' में सिटी टॉपर का खिताब अर्जित कर पूरे देश में लखनऊ का गौरव बढ़ाया है। अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित इस प्रतिष्ठित परीक्षा में कनिष्का ने ऑल इण्डिया 18वीं रैंक अर्जित कर अपने मेधात्व का परचम लहराया है। यह जानकारी सी.एम.एस. के मुख्य जन–सम्पर्क अधिकारी श्री हरि ओम शर्मा ने दी है। श्री शर्मा ने बताया कि सी.एम.एस. के सर्वाधिक 13 मेधावी छात्रों ने इस वर्ष ए. आई.एल.ई.टी. में चयनित होकर विद्यालय का नाम रोशन किया है। सी.एम.एस. के इन आठ होनहार छात्रों में कनिष्का मित्तल, यशी किशोर, दिव्यांश सिंह, अभिनव रघवंशी, यश रावत, अनन्या राज सिंह, अंतरा शुक्ला, आयुषी राठौर, अर्चित यादव, हिमांशी वर्मा, आर्या उपाध्याय, समृद्धि वर्मा एवं देवल तिवारी शामिल हैं। सी.एम.एस. संस्थापक व प्रख्यात शिक्षाविद् डा. जगदीश गाँधी एवं सी.एम.एस. प्रेसीडेन्ट प्रो. गीता गाँधी किंगडन ने सी.एम.एस. के इन मेधावी छात्रों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी हैं। श्री शर्मा ने बताया कि ए.आई.एल.ई.टी. में चयन के उपरान्त अब ये छात्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, दिल्ली एवं इससे सम्बद्ध कालेजों में बी.ए.एल.एल.बी. आनर्स कोर्स में एडमीशन लेकर अपने सपनों को साकार कर पायेंगे। सी.एम.एस. के इन मेधावी छात्रों ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता–पिता एवं शिक्षकों के अलावा सी.एम.एस. के शान्तिपूर्व व ईश्वरीय एकता से ओतप्रोत शैक्षिक वातावरण को दिया है। श्री शर्मा ने बताया कि सी.एम.एस. अपने छात्रों को आई.एस.सी. की पढ़ाई के दौरान ही छात्रों को प्रोफेशनल कोर्सो की तैयारी हेतु मार्गदर्शन एवं वातावरण उपलब्ध कराता है, यही कारण है कि विद्यालय के मेधावी छात्र प्रतिवर्ष देश–विदेश की प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता अर्जित लखनऊ का गौरव बढ़ा रहे हैं।

भारत में नई किआ सॉनेट का वर्ल्ड प्रीमियररू सबसे प्रीमियम कॉम्पैक्ट एसयूवी दमदार नए डिजाइन, एडैस और मानक के रूप में 6 एयरबैग के साथ लॉन्च हुई

लखनऊ। भारत की अग्रणी मास प्रीमियम कार निर्माता, किआ ने अपने दूसरे सबसे ज्यादा बिकने वाले इनोवेशन, द न्यू सॉनेट के नए अवतार को सबसे पहले भारत में पेश किया है। अधिक मजबूत और स्पोर्टी सॉनेट को तकनीक–प्रेमी और वन–स्टॉप मीबिलिटी समाधान चाहने वाले आधुनिक जोड़ों और पेशेवरों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। इसमें 10 ऑटोनॉमस सुविधाओं वाला एडैस दिया गया है, जिनमें फ्रंट कोलिजन अवॉइडेंस असिस्ट, लीडिंग व्हीकल डिपार्चर अलर्ट, और लेन फॉलोइंग असिस्ट जैसे कुछ नाम शामिल हैं। मजबूत 15 हाई–सेफ्टी सुविधाओं के साथ, सॉनेट अब 25 से अधिक सेफ्टी फीचर्स का दावा करती है। भारत में नई सॉनेट के दूसरे वर्ल्ड प्रीमियर पर, किआ इंडिया के प्रबंध निदेशक और सीईओ ताए–जिन पार्क ने कहा, "सेल्टॉस के बाद भारत में हमारी सफलता के सफर में सॉनेट की खास जगह है। अभूतपूर्व सुविधाओं और डिजाइन के साथ भारत में प्रीमियर होने के बाद, यह सरहदों को पार कर गया है और अब इसे 100 से अधिक देशों में निर्यात किया जाता है, जहां हमें 3.68 लाख ग्राहकों का विश्वास पाने पर गर्व है जो वास्तव में सॉनेट के ड्राइविंग अनुभव का आनंद लेते हैं। नई सॉनेट के साथ, हमारा उद्देश्य इसे खरीदने के किफायती अनुभव के साथ इसकी प्रीमियम सुविधाओं को सहजता से एकीकृत करना है, जिसमें रखरखाव का न्यूनतम खर्च और उल्लेखनीय रूप से उच्च रीसेल वैल्यू की खूबी भी सहजता से मिली है। यह अनूठा संयोजन आधुनिक उपभोक्ताओं के व्यापक ग्राहकवर्ग के साथ जुड़ने के लिए तैयार है। हमारी महत्वाकांक्षा नई सॉनेट को पेश करके कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में अग्रणी स्थिति सुरक्षित करना है।नई सॉनेट अपने सेगमेंट में 15 मानक सुरक्षा सुविधाएं पेश करने वाली एकमात्र कॉम्पैक्ट एसयूवी भी बन गई है। इसके अलावा, इसमें 10 बेस्ट–इन–सेगमेंट सुविधाएं भी दी गई हैं, जिसमें डुअल स्क्रीन कनेक्टेड पैनल डिजाइन, रियर डोर सनशेड कर्टन, ऑल डोर पावर विंडो वन टच ऑटो अपब्डाउन, सुरक्षा के साथ, और स्मार्टप्योर एयर प्यूरीफायर वायरस और बैक्टीरिया सुरक्षा के साथ शामिल है। कैरेंस के साथ उद्योग में पहली बार मानक 6 एयरबैग और सेल्टॉस के साथ सेगमेंट में पहली बार एयरबैग पेश करने के बाद, किआ एक बार फिर सुरक्षा मानदंडों को फिर से परिभाषित कर रहा है। नई सॉनेट में मानक सुविधा के रूप में 6–एयरबैग को शामिल करके किआ भारत में अपने सभी उत्पादों में 6 या 8 एयरबैग पेश करने वाला सबसे युवा ब्रैंड बन गया है।

इसके अलावा, किआ टेक्नोलॉजी से संचालित एक नवीन पुरस्कार–आधारित सुरक्षा शिक्षा पहल, शेकिआ इंस्पायरिंग ड्राइव प्रोग्रामश् या के.आई.डी. शुरू कर रही है। शेकिआ कनेक्टश् ऐप के माध्यम से एक्सेसिबल, यह कार्यक्रम किआ मालिकों के ड्राइविंग व्यवहार का मूल्यांकन करता है, जैसे सीटबेल्ट का उपयोग, अचानक ब्रेक लगाना, गति सीमा का पालन करना और बहुत कुछ, और इनके आधार पर उन्हें इकोस्कोर प्रदान करता है जिसे पुरस्कार के लिए रिडीम किया जा सकता है। इस कार्यक्रम को शुरुआत में किआ सॉनेट मालिकों के लिए पेश किया जा रहा है।

विद्यार्थी प्रतिभा उत्सव 22 दिसम्बर को होगा,छात्र दिखाएंगे प्रतिभा

लखनऊ। सामाजिक संस्था सोसायटी ऑफ कॅरियर टेक्नोलॉजी (सोक्ट) एवं जन विकास महासभा के तत्वावधान में आगामी 22 दिसम्बर से तीन दिवसीय विद्यार्थी प्रतिभा उत्सव एन्आरएलसी ट्रेनिंग संस्थान सेक्टर–जी जानकीपुरम के ऑडिटोरियम में शुरू हो रहा है। मुख्य आयोजक पंकज तिवारी ने बताया कि 22 दिसम्बर को उत्सव की शुरूआत सुबह दस बजे होगा। इसके बाद विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थी आर्ट, ड्राइंग, गायन, नृत्य, वाद्ययंत्र, स्पीच और कबाड़ से जुगाड़ क्षेत्रों में अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन करेंगे। जो 24 दिसम्बर सुबह दस बजे से दोपहर एक बजे के बीच जारी रहेगी। इस उत्सव कार्यक्रम के दौरान पौधरोपण, पर्यावरण एवं जल संरक्षण संकल्प, निरूशुल्क स्वास्थ्य शिविर, शिक्षा एवं कैरियर मार्गदर्शन, आत्मनिर्भर भारत के महत्व पर जागरूकता, नशामुक्त समाज का संकल्प दिलाने पर भी कार्यक्रम भी आयोजित होगा।

विश्वविद्यालय के 31 छात्रों का सीएसआईआर व आईआईटीआर मे इंटर्नशिप शुरू

लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय के एमएससी रसायन विज्ञान और एमएससी फार्मास्युटिकल रसायन विज्ञान के सेमेस्टर तृतीय के इकतीस छात्रों के तीसरे बैच ने 14 दिसंबर से सीएसआईआर व भारतीय विषविज्ञान अनुसंधान संस्थान (आईआईटीआर) में अपना इंटर्नशिप कार्यक्रम शुरू किया। यह इंटर्नशिप कार्यक्रम उनके सेमेस्टर तीसरे पाठ्यक्रम का हिस्सा है। इन सभी छात्रों को सीएसआईआर एकीकृत कौशल विकास पहल में शामिल किया गया है। जहां उन्हें विभिन्न व्यापक क्षेत्रों मुख्य रूप से इंस्ट्रूमेंटेशन और रासायनिक विश्लेषण पर कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त होगा। इस प्रशिक्षण में मानक तैयारी का प्रदर्शन, मास स्पेक्ट्रोमीटर, परमाणु प्रतिदीप्ति स्पेक्ट्रोस्कोपी, गैस क्रोमैटोग्राफी, यूवी दृश्यमान जैसे विभिन्न उपकरणों का दौरा और प्रदर्शन शामिल होगा। वे बौद्धिक संपदा अधिकारों और दस्तावेजीकरण के महत्व और उपलब्ध गुणवत्ता प्रबंधन प्रणालियों एवं अन्य बातों के बारे में भी सीखेंगे। आईआईटीआर में इंटर्नशिप कार्यक्रम का उद्घाटन 14 दिसंबर को निदेशक की ओर से आईआईटीआर के प्रमुख वैज्ञानिक डॉ. रवि राम द्वारा किया गया था। उन्होंने आईआईटीआर में कौशल विकास गतिविधियों और प्रशिक्षण सुविधाओं का अवलोकन प्रस्तुत किया। डॉ. रचना कुमार ने अतिथियों का स्वागत किया और प्रतिभागियों को दी जा रही। डॉ. अखिलेश कुमार यादव, वैज्ञानिक आईआईटीआर ने प्रशिक्षण कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण दिया। लखनऊ विश्वविद्यालय के रसायन विज्ञान विभाग के प्रमुख प्रोफेसर अनिल मिश्रा ने इस तरह के प्रशिक्षण के महत्व पर जोर दिया और छात्रों से इस अवसर का अधिकतम लाभ उठाने को कहा। कार्यक्रम का संचालन रसायन विज्ञान विभाग की ओर से डॉ. ओम प्रकाश ने किया।

सम्पादकीय

संसद में छोड़े गये 'पीले रंग' में छिपे 'काले उद्देश्य' का पता लगाना बेहद जरूरी है

शीतकालीन सत्र के 10वें दिन भारतीय संसद के अंदर शायद कुछ बहुत बड़ा होना मुकर्रर था क्योंकि 22 बरस पहले आतंकवादियों द्वारा दिया एक नासूर जख्म जो प्रत्येक 13 दिसबंर की तारीख के दिन याद करके हरा हो जाता है। खैर, गनीमत ये समझें कि संभावित घटना 'पीले रंग' तक ही सीमित रही, वरना कुछ 'काला' भी हो सकता था। 13 तारीख वैसे भी संसदीय परंपरा के लिए 'काली तारीख' ही है। केंद्र सरकार इस अधूरी घटना को हल्के में कतई न ले। नहीं, तो पीले रंग में छिपी ये संदेशवाहक घटना कभी भी पूर्ण घटना में तब्दील हो सकती है। इतना सतर्क हो जाना चाहिए कि दुश्मन घात लगाए बैठा है इसलिए अभी से इस तस्वीर को गंभीरता से लेने की आवश्कता है। आरोपियों की बुनी साजिश की जड़ तक घुसना होगा? उनका मकसद दहशत फैलाना मात्र था या कुछ और? फिलहाल ऐसे तमाम सवाल खड़े हो चुके हैं। पर, अव्वल तो इस घटना को घोर लापरवाही और सुरक्षातंत्र की नाकामी ही कहेंगे। चाकचौबंद सुरक्षा–व्यवस्था से कहां चूक हुई, इसकी भी समीक्षा किए जाने की जरूरत है।

बहरहाल, संसद तो नई–नवेली है, जिसे अत्याधुनिक सुरक्षा तकनीकों से लैस बताया जाता है। लेकिन घटना जिस अंदाज में घटी उससे साफ पता चलता है कि साजिश की तासीर कुछ और थी। आरोपी सामान्य हैं या असामान्य प्रवृत्ति के, ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। पर, लोग अंदेशा ऐसा भी लगा रहे हैं कि कहीं 22 साल पहले 13 दिसंबर को जो घटना संसद में घटी थी ये उसकी पुनरावृत्ति तो नहीं? या फिर उसका पार्ट–2 की चेतावनी है। इस लापरवाही की जवाबदेही किसकी हो, ये बिना देर किए सुनिश्चित हो। एक थ्योरी ये समझ में नहीं आती कि आखिर शीतकालीन सत्र को चले कई दिन हो चुके हैं। पर, हरकत संसद हमले की बरसी के दिन ही क्यों होती है? अचंभित कर देने वाली बात एक ये भी है कि आरोपियों ने भगत सिंह के स्टाइल को क्यों कॉपी किया? पीला धुंआ फैलाकर, नारे लगाना, तानाशाही से मुक्ति मिले? आखिर ये सब किस ओर इशारा करता है। कौन है घटना के पीछे, उसे सामने लाना ही होगा और आरोपी ने जो तानाशाही से आजादी के नारे लगाए हैं उसके निहितार्थ भी सार्वजनिक होने चाहिए।

आरोपियों का हमले की बरसी के दिन 'संसद अटैक–2' का संदेश देना निश्चित रूप से बेचौन करता है। पीले रंग में छिपे काले संदेश को समझा होगा। दुश्मन अंदरूनी है या बाहरी? उन्हें खींचकर बाहर निकालना होगा। प्रतीत ऐसा होता है कि आरोपी सिर्फ मोहरा मात्र हैं। मास्टर माइंड कोई और ही है? जब से नई संसद में सत्र और संसदीय कार्य शुरू हुए हैं। संसद सदस्य अपनी सुरक्षा के प्रति निश्चित और बेखबर हैं। क्योंकि संसद की सुरक्षा सेफ्टी मानकों के लिहाज से अत्याधुनिक बताई जाती है। संसद की एक–एक ईंट और चप्पे–चप्पे पर सुरक्षा पहरा बिछा हुआ है। खुदा न खास्ता इंसानी सुरक्षा तंत्र से अगर कोई चूक भी हो जाए, तो पूरी बिल्डिंग तीसरी आंख यानी सीसीटीवी कैमरों से लैस है। कोई संदिग्ध क्या, परिंदा भी पर नहीं मार सकता। पर, अब इन मौखिक और कागजी सुरक्षा व्यवस्था पर संसद सदस्यों को एतबार नहीं रहा। क्योंकि उन सभी को धता बताते हुए आरोपी विजिटर बनकर आसानी से भीतर घुस गए और अपने मंसूबों को अंजाम दे दिया।

गनीमत ये समझें कि घटना के दौरान आरोपियों के हाथ में सिर्फ 'स्मोक बम' ही थे, अगर असलहा–वगैरह होता तो वो इस्तेमाल भी कर सकते थे। क्योंकि जब वो सुरक्षा तंत्र की आंखों में धूल झोंककर आपत्तिजनक वस्तुएं अंदर ले जा सकते हैं तो बंदूक–बारूद क्यों नहीं? इसलिए घटना को सबसे पहले सुरक्षा चूक ही कहेंगे। जबरदस्त सुरक्षा पहरे को बेवकूफ बनाकर 'स्मोक बम' फेंककर संसद के भीतर आरोपी अफरा–तरफी मचा देते हैं। बकायदा विजिटर बनकर संसद की कार्यवाही देखने पहुंचते हैं। दर्शक दीर्घा में करीब चार–पांच घंटे बिताते हैं और लंच से पहले अचानक छलांग लगाकर सांसदों की कुसिर्यों तक जाते हैं। पीले रंग का 'स्मोक बम' फोड़ देते हैं। 'तानाशाही से आजादी' जैसे नारे लगाते हैं। ये पूरा वाकया तकरीबन चालीस से पैंतालीस मिनट तला। सुरक्षाकर्मियों के पहुंचने से पहले दो सांसद हनुमान बेनीवाल और मलूक नागर हिम्मत दिखाकर उन्हें दबोचते हैं और उन्हें सुरक्षा कर्मियों के हवाले करते हैं।

आरोपी मैसूर से भाजपा सांसद प्रताप सिम्हा की सिफारिश पर कार्यवाही देखने पहुंचे। वो झूठ बोल रहा है या सच? ये जानने के लिए उसका नार्को, पॉलीग्राफ और ब्रेन मैपिंग टेस्ट जरूर करवाना चाहिए। अगर कोई गहरी साजिश है भी, जैसा कि कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी दावा कर रहे हैं, तो उसे पता लगाने की दरकार है। संसद में सुबह तक सब कुछ नॉर्मल था। 22 वर्ष पूर्व हुए हमले की बरसी थी जिस पर सभी सांसदों ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी और उसके बाद रोजाना की भांति सत्र की कार्यवाही में हिस्सा लेने जाते हैं। किसी को थोड़ा–सा भी अंदेशा नहीं था कि नई संसद में भी कोई ऐसी भी हरकत कर सकता है। संसद सदस्य आश्वस्त थे कि नई संसद सुरक्षा मानकों के चलते अभेद्य है। बावजूद आरोपी चार नंबर गेट से विजिटर बनकर प्रवेश कर जाता है। क्या आरोपी 'स्मोक बम' के जरिए कोई संदेश फैलाना चाहता था, ये फिर उसे मात्र पब्लिसिटी चाहिए थी। हालांकि ऐसे सभी सवालों की लंबी लिस्ट बनाकर स्थानीय पुलिस और अन्य जांच एजेंसियां पूछताछ में लगी हैं। लेकिन विपक्षी दल किसी बड़ी घटना होने की आशंका जता रहे हैं। उनकी आशंकाओं को ध्यान में रखकर भी जांच करनी चाहिए, इसके अलावा उसी वक्त बाहर भी एक युवती–युवक तानाशाही से आजादी के नारे लगा थे, उनसे भी कड़ाई से पूछताछ होनी चाहिए। देशवासियों में ये संदेश बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए कि जब संसद ही सुरखित नहीं तो वो भला कैसे सुरक्षित होंगे।

धारा 370 को सर्वोच्च न्यायालय ने किया निरस्त, पर अनेक मुद्दे रह गये अनुत्तरित

सॉलिसिटर–जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया था कि अगस्त 2019 में धारा 370 को निरस्त करने के बाद जम्मू–कश्मीर को दिया गया केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा केवल एक अस्थायी उपाय था। उस वक्त सरकार ने कहा था कि वह उग्रवाद और आतंकवाद को खत्म करने के लिए यह कदम उठा रही है। अब मोदी सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्या आतंकवाद खत्म हो गया है, विशेषकर इसलिए कि सरकार द्वारा उठाये गये कदम को अस्थायी बताया गया था।भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 11 दिसंबर को अपने फैसले में संविधान की धारा 370 को निरस्त करने को बरकरार रखा, जिसके बहुआयामी निहितार्थ हैं। शीर्ष अदालत ने धारा 370 की उपधारा (बी) को हटा दिया, लेकिन उसने सीधे तौर पर यह घोषणा नहीं की कि धारा 370 का अस्तित्व समाप्त हो जायेगा। उपधारा (बी) के अस्तित्व समाप्त होने की पृष्ठभूमि में, यह माना जा सकता है कि धारा 370 अप्रचलित हो गई है और अस्तित्वहीन है। बेशक, आरएसएस, भाजपा और मोदी जम्मू–कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाली धारा 370 के प्रावधानों को निरस्त करने की अपनी योजना की सफलता का दावा कर सकते हैं और इसे 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान एक बड़ी राजनीतिक जीत के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास कर सकते हैं। परन्तु संभवतरू हिंदू मध्यम वर्ग के मतदाताओं और भक्तों के एक वर्ग के मानस को प्रभावित करने में सफल होने पर, यह निकट भविष्य में राजनीतिक कार्रवाइयों और जवाबी प्रतिक्रियाओं की एक श्रृंखला शुरू कर देगा।

पीठ ने फिर भी फैसला सुनाया कि श्जम्मू–कश्मीर की कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं हैश और 1947 के विलय पत्र के माध्यम से उसने भारत संघ को श्पूर्ण रूप से और अंततरू आत्मसमर्पित कर दिया था, और धारा 370 एक अस्थायी उपाय मात्र था। निश्चित रूप से यह जम्मू–कश्मीर के आम लोगों की गलती नहीं है कि उनके पास श्आंतरिक संप्रभुताश नहीं है जो अन्य राज्यों द्वारा प्राप्त संप्रभुता से अलग है। यदि जम्मू–कश्मीर ने पूरी तरह से और अंततरू आत्मसमर्पण कर दिया था, तो सरकार ने रक्षा, विदेशी मामलों और मौद्रिक लेनदेन को 370 के दायरे में क्यों रखा और बाकी सब कुछ स्थानीय प्रशासन पर छोड़ दिया, जिसे दिन–प्रतिदिन शासन करना था। ऐसी स्थिति में सभी निर्णय और प्रशासनिक कार्रवाइयां अप्रासंगिक मानी जायेंगी और उनकी कोई संवैधानिक या कानूनी वैधता नहीं होगी। संप्रभुता एक व्यापक शब्द है और यह भारतीय संदर्भ तक ही सीमित नहीं है। वास्तव में यह एक राजनीतिक अवधारणा है जो प्रमुख शक्ति या सर्वोच्च सत्ता को संदर्भित करती है। राजशाही में, सर्वोच्च शक्ति संप्रभु या राजा में निहित होती है। आधुनिक लोकतंत्रों में, संप्रभु शक्ति लोगों के पास होती है और इसका प्रयोग प्रतिनिधि निकायों के माध्यम से किया जाता है। जाहिर है कि जम्मू–कश्मीर में एक विधानसभा थी, इसके सदस्यों का चुनाव राज्य की जनता द्वारा किया जाता था। इसमें कोई संदेह नहीं कि राष्ट्रपति ने इसे रद्द करने का आदेश दिया। लेकिन उन्होंने गणतंत्रीय लोकतंत्र की रीतियों और मर्यादाओं का पालन करते हुए मोदी सरकार की कैबिनेट के सुझाव पर इसे मंजूरी दे दी। इससे यह भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि मोदी सरकार ने किसी गलत इरादे से यह कवायद नहीं की, बल्कि सरकार ने साफ शब्दों में सर्वोच्च न्यायलय को अपनी मजबूरियां बताईं, पर न्यायालयी आदेश में मजबूरी नहीं झलकती है। चूंकि इस मामले में मोदी सरकार ने अपने कैबिनेट फैसले के साथ राष्ट्रपति से संपर्क किया था, जाहिर है, राष्ट्रपति को इस धारा के दूसरे प्रावधान के तहत राज्य सरकार की ओर से कार्य करने वाली राज्य सरकार या केंद्र सरकार की सहमति सुरक्षित करने की आवश्यकता नहीं थी। 370(1)(डी) संविधान के सभी प्रावधानों को जम्मू और कश्मीर में लागू करते समय, क्योंकि शक्ति का ऐसा प्रयोग धारा 370(3) के तहत शक्ति के प्रयोग के समान प्रभाव रखता है, उसके लिए राज्य सरकार की सहमति या सहयोग आवश्यकता नहीं थी। सॉलिसिटर–जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया था कि अगस्त 2019 में धारा 370 को निरस्त करने के बाद जम्मू–कश्मीर को दिया गया केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा केवल एक अस्थायी उपाय था। उस वक्त सरकार ने कहा था कि वह उग्रवाद और आतंकवाद को खत्म करने के लिए यह कदम उठा रही है। अब मोदी सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्या आतंकवाद खत्म हो गया है, विशेषकर इसलिए कि सरकार द्वारा उठाये गये कदम को अस्थायी बताया गया था। गृह मंत्रालय द्वारा राज्यसभा में जारी एक हालिया बयान में स्वीकार किया गया है कि जम्मू और कश्मीर में 2018 से 2022 के बीच 761 आतंकवादी घटनाएं देखी गई। इन सभी हमलों में 174 नागरिकों की मौत हुई है। इसके अलावा राज्य में राजनीतिक अस्थिरता भी बनी हुई है। मोदी सरकार ने नेताओं का भरोसा खो दिया है। इनमें से कई लोग घर में नजरबंद रह रहे हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि संविधान पीठ के न्यायाधीशों में से एक ने धारा 370 के निरस्तीकरण को बरकरार रखते हुए कम से कम 1980 के दशक से जम्मू–कश्मीर में राज्य और राज्य के बाहर के सक्रिय तत्वों द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच करने और सुलह के उपायों की सिफारिश करने के लिए सच्चाई और सुलह आयोग की स्थापना की सिफारिश की। यह कहते हुए कि आगे बढ़ने के लिए, घावों को ठीक करने की आवश्यकता है, सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठता में दूसरे नंबर पर न्यायमूर्ति संजय किशन कौल ने कहा, स्मृति के लुप्त होने से पहले, इस आयोग का गठन शीघ्रता से किया जाना चाहिए। इसे समयबद्ध तरीके से किया जाना चाहिए। युवाओं की एक पूरी पीढ़ी पहले से ही अविश्वास की भावनाओं के साथ बड़ी हुई है और क्षतिपूर्ति का हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य उन्हीं के प्रति है। हालांकि जम्मू–कश्मीर के लोग निराश हैं, लेकिन इस आदेश में आशा की एक उज्ज्वल किरण भी है। पीठ ने मोदी सरकार को जम्मू–कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने का निर्देश दिया है। यह जितनी जल्दी हो सके किया जायेश इसने कहा और साथ ही उसने चुनाव आयोग को 30 सितंबर, 2024 तक जम्मू और कश्मीर विधानसभा के चुनाव कराने का निर्देश दिया। एक बार जब कश्मीर के लोग अपने मार्गदर्शन और भविष्य का फैसला करने के लिए अपनी सरकार बना लेते हैं, तो वे घाटी में बाहरी लोगों के जमीन खरीदने के प्रावधान को खत्म कर सकते हैं। यह उन मुख्य कारकों में से एक है जिसने आरएसएस और भाजपा नेतृत्व को सुरक्षा प्रदान करने वाले 370 को निरस्त करने के लिए प्रेरित किया। यदि अदालत को लगता है कि धारा 370 में संशोधन के लिए संसद द्वारा धारा 367 का सहारा लेना संवैधानिक रूप से अमान्य था तो वह इसे निरस्त करने की मंजूरी कैसे दे सकती है। इसने यह भी कहा कि धारा 370 को धारा 367 के तहत शक्ति के प्रयोग से संशोधित नहीं किया जा सकता है, जो केवल एक व्याख्यात्मक खंड है और कोई संशोधन शक्ति या प्रावधान नहीं है। गलत तो गलत है। दुर्भावनापूर्ण राजनीतिक इरादे को रेखांकित करना बहुत मुश्किल है। मोदी सरकार इस बारे में कोई ठोस और उचित स्पष्टीकरण नहीं दे सकी कि किस वजह ने उसे राज्य को विभाजित करने के लिए प्रेरित किया। यही कारण था कि कांग्रेस ने जम्मू–कश्मीर के विघटन पर निर्णय लेने में सर्वोच्च न्यायालय की अनिच्छा पर निराशा व्यक्त की, और कहा कि वह धारा 370 को निरस्त करने के फैसले से सम्मानपूर्वक असहमत है। इस पृष्ठभूमि में कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य अभिषेक मनु सिंघवी ने जानना चाहा कब तक केंद्र सरकार रिमोट कंट्रोल से राज्य पर शासन करने का इरादा रखती है? डर किस बात का है? सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में विरोधाभास है। हालांकि इसमें कहा गया है कि वे राज्य को केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के फैसले की वैधता पर फैसला नहीं करेंगे। इसे एक खुला मामला घोषित करते हुए उन्होंने लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने को उचित ठहराया। दुर्भाग्य से कश्मीरी लोगों के घावों पर मरहम लगाने का अवसर खो गया है। कश्मीर के लोगों ने सब कुछ अपने भाग्य पर छोड़ दिया है। उन्हें सुरंग के अंत में प्रकाश की कोई झिलमिलाहट दिखाई नहीं देती। यही कारण है कि वे अच्छी या प्रतिकूल टिप्पणी करने से बचते रहे। शीर्ष अदालत के इस आदेश से राजनीतिक नेताओं और आम लोगों को राहत नहीं मिली है। उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती जैसे नेता फैसले के बाद के विकल्प तलाश रहे होंगे।

सब कुछ धुंधला है

सब कुछ धुंधला है, धुंधला है, मैं सारे ये गम भुला के घूम रहा, ये गीत पिछले साल आए एक अलबम का है और युवाओं के बीच खासा मशहूर है। इस गीत की जो शुरुआती पंक्तियां हैं, वो देश की सियासत और देश के भविष्य की सटीक बयानी कर रही हैं। राजनैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक तौर पर हम क्या थे, क्या बनाए जा चुके हैं और अब आगे कैसे होंगे, इस बारे में विचार करें तो वाकई सब धुंधला ही नजर आएगा। आज से 20–30–50 साल पहले के भारत को देखें और आज से उसकी तुलना ईमानदारी से करें तो पता चलेगा कि कैसे संविधान में वर्णित मूल्यों को बड़े शातिराना तरीके से किनारे करते हुए हिंदुत्व की जड़ें गहरी की गईं, फिर देश में नफरत की अमर बेल फैलाई गई और अब समाज में जो स्पष्ट विभाजन हो चुका है, उसे सामान्य साबित किया जा रहा है। और इसका दोष अकेले भाजपा या संघ पर नहीं डाला जा सकता, इस देश के जितने राजनैतिक दल हैं, कांग्रेस समेत, वो सब इसमें भागीदार रहे हैं। क्योंकि अगर भाजपा ने 90 के दशक में ऐलान किया था कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तो बाकी दलों ने भी अपनी कमियों और कमजोर फैसलों के कारण यह सुनिश्चित किया कि भाजपा मंदिर वहीं बनाए और केवल यहीं पर न रुके, बल्कि जम्मू–कश्मीर, मथुरा, काशी और इस तरह के तमाम मंसूबे जो नागपुर ने पाल रखे थे, उन्हें पूरा करके दिखाए। देश में पिछले 10 सालों से भाजपा की पूर्ण बहुमत वाली सरकार है। ये पूर्ण बहुमत भाजपा को 2014 में 31 प्रतिशत वोट के साथ मिला और 2019 में 38 प्रतिशत वोट के साथ। कांग्रेस समेत बाकी दल यही कहकर खुश होते रहे कि भाजपा को बहुमत मिलने के बावजूद बचे 60–70 प्रतिशत वोट हमारे पास रहे। लेकिन इन वोटों के बावजूद सत्ता क्यों नहीं मिली, क्यों विधानसभा चुनावों में जीत नहीं मिली, इस पर कोई विचार–विमर्श नहीं किया गया। ये विचारधारा और राजनैतिक प्रतिबद्धता का धुंधलापन है, जिसे केवल भाजपा को भला–बुरा कहकर दूर नहीं किया जा सकता। उसके लिए विपक्षी दलों के पास स्पष्ट नजरिया होना चाहिए। खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि हाल में मिली विधानसभा चुनावों में हार के बावजूद अपने प्रदर्शन को लेकर कोई गंभीर मंथन कांग्रेस में दिखाई नहीं दे रहा है। अभी कांग्रेस इसी में खुश है कि भाजपा को मुख्यमंत्री तय करने में एक हफ्ते से अधिक वक्त लग गया। भाजपा ने तीनों राज्यों में एकदम से नए चेहरों को लाकर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठा दिया है, तो अब भाजपा में बगावत हो सकती है, इसी ख्याल से कांग्रेस प्रसन्न हो रही है। इसी को वैचारिक दिवालियापन या प्रतिबद्धता की कंगाली कहते हैं। ये सही बात है कि धुंधलापन भाजपा के स्तर पर भी है। अगर दृष्टिकोण की स्पष्टता होती तो मुख्यमंत्री चयन में इतना वक्त नहीं लगता। जीते हुए विधायकों को यह तय करने दिया जाता कि उन्हें किसे विधायक दल का नेता चुनना है। मगर सत्ता के केन्द्रीकरण के आदी हो चुके प्रधानमंत्री मोदी और उनके सिपहसालार अमित शाह किसी भी तरह अपनी पकड़ कमजोर नहीं करना चाहते। इसलिए तीनों राज्यों में पूर्व मुख्यमंत्रियों और अन्य दिग्गजों को प्रतीक्षा की कतार में छोड़कर नए चेहरों को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप दी। अब ये मुख्यमंत्री खुद को उपकृत मानते हुए आलाकमान के सामने वफादारी साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद लोकसभा चुनाव की सभी सीटें अपनी पार्टी के खाते में करने के लिए एड़ी–चोटी का जोर लगा देंगे। 2014 के बाद से ऐसा ही हुआ है कि लोकसभा के बाद विधानसभा चुनावों में जीत मिली, फिर विधानसभाओं के जरिए राज्यसभा में पार्टी की ताकत बढ़ी, उसके बाद मनमाने फैसले लेने में आसानी हुई, फिर दोबारा लोकसभा में जीत मिली और फिर से विधानसभा चुनावों में जीत मिली है। यही क्रम चला तो अगले चुनाव यानी 2024 में भाजपा की जीत के दावे खारिज नहीं किए जा सकते। और अगर ये दावे सही हुए तो फिर उसके बाद के विधानसभा चुनावों में जीत की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। यानी एक जीत से दूसरी जीत का मार्ग प्रशस्त होगा। उससे भाजपा की ताकत बढ़ेगी, लेकिन क्या देश ताकतवर बन पाएगा। क्या भाजपा की ताकत से डर कर चीन अरुणाचल से लेकर लद्दाख तक अपने कब्जे के इरादे को छोड़ देगा, क्या भाजपा की ताकत रुपए की ताकत बढ़ा देगी, क्या हमारे देश के विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा के सम्मानजनक केंद्र बन जाएंगे, क्या खेतों में फसलें लहलहाने लगेंगी, क्या गंगा का मैल भाजपा की ताकत पाकर दूर हो जाएगा, क्या हिमालय की बर्फ इतनी सख्त हो जाएगी कि अपनी तराई में पल रहे गांवों की रक्षा कर सके, क्या हवा में घुला प्रदूषण भाजपा की आंधी से दूर हो जाएगा, क्या देश के युवाओं को नौकरी के लिए परीक्षा और नियुक्ति के इंतजार के जंजाल से आजादी मिल जाएगी। ऐसे सवालों की लंबी सूची है और जवाब तलाशने के लिए पिछले 10 सालों के भाजपा शासन को देखें तो निराशा ही होगी। जो काम 10 सालों में नहीं हुआ, वो अगले 10 सालों में भी कैसे हो पाएगा। कांग्रेस और बाकी सभी विपक्षी दलों को इन्हीं सवालों के साथ जनता के बीच जाना चाहिए। मगर अभी फिर से विमर्श के मुद्दे भाजपा ही दे रही है, वही नैरेटिव सेट कर रही है। जैसे अभी संसद में केन्दीय गृहमंत्री अमित शाह ने पं.नेहरू की जम्मू–कश्मीर को लेकर गलतियां बताईं। एक उलझे हुए जटिल ऐतिहासिक मुद्दे का अति सरलीकरण करते हुए बताया कि केवल दो दिन नेहरू रुक जाते तो पीओके बनता ही नहीं। अमित शाह ने ये बात बिल्कुल मोदीजी की तर्ज पर कही। जैसे नोटबंदी के लिए श्री मोदी ने कह दिया था कि इससे भ्रष्टाचार दूर होगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, काला धन मिट जाएगा। और जब कांग्रेस के सांसद के घर 3 सौ करोड़ से अधिक की नगदी मिलती है, तो श्री मोदी इसे कांग्रेस का भ्रष्टाचार बताते हुए ये बिल्कुल भूल जाते हैं कि इतनी नकदी मिलने का मतलब है नोटबंदी फेल हो गई है। कांग्रेस सांसद से पहले यूपी में इत्र के व्यापारी के घर भी ऐसे ही रकम पकड़ाई थी, मप्र में कुछ सरकारी अधिकारियों के घर ऐसे ही नोट निकले थे। यानी भ्रष्टाचार एक पार्टी तक सीमित नहीं है और इतनी आसानी से नहीं मिट सकता, जैसा प्रधानमंत्री मोदी दावा करते आए हैं। ऐसे ही जम्मू–कश्मीर की समस्या केवल पीओके बनने या अनुच्छेद 370 के कारण नहीं हुई, उसके लिए बहुत सारे अन्य कारक भी जिम्मेदार रहे, जिनका जिक्र अमित शाह ने अपनी राजनैतिक सुविधा के लिए नहीं किया। राहुल गांधी ने कहा भी कि अमित शाह इतिहास से अनजान हैं। मैं उनसे इतिहास जानने की उम्मीद नहीं कर सकता, उन्हें इसे दोबारा लिखने की आदत है...। बिल्कुल सही कहा। लेकिन इससे आगे होना ये चाहिए कि अगर अमित शाह या भाजपा इतिहास को दोबारा लिखने की कोशिश में हैं, तो कांग्रेस और बाकी विपक्षी दल उस कोशिश को रोकने में जुट जाएं। ये काम तथ्यों को जनता के बीच पहुंचाने से होगा। दस सालों में ये दिख गया कि मीडिया भाजपा के साथ है, सोशल मीडिया पर भी उसी का जोर है। तो फिर एक ही तरीका बचा है कि जनता तक सीधी पहुंच कायम की जाए। टीवी चौनल में दो–चार प्रवक्ता एंकरों को जवाब देते हैं और फिर उसकी वाहवाही सोशल मीडिया पर होती है, इससे कुछ हासिल नहीं होना है। इस समय पूरे इंडिया गठबंधन को ऐसे नेताओं की जरूरत है जो जनता के बीच जाकर उन्हें तथ्यों के साथ इतिहास बताएं, संविधान में दिए गए उनके अधिकारों को आसान भाषा में समझाएं और ये भी बताएं कि मंदिर–मस्जिद की लड़ाई में उनका कितना नुकसान हो चुका है और कितना नुकसान होगा। प्रो.मनोज झा, जवाहर सरकार, गौरव वल्लभ, आलोक शर्मा जैसे और लोग इंडिया को तलाशने होंगे, जो जनता को भाजपा की चालाकियां तथ्यों के साथ दिखा सकें। ये एक लंबी प्रक्रिया है, मगर राजनैतिक बदलाव जनता को साथ लिए बिना नहीं हो पाएगा। इसके अलावा कांग्रेस को सगों और ठगों का फर्क भी समझना होगा। क्या यह महज संयोग है कि कांग्रेस की हार के बाद ही शर्मिष्ठा मुखर्जी की अपने पिता प्रणव मुखर्जी पर लिखी किताब विमोचित होती है और उसके वही हिस्से मीडिया के जरिए चर्चा में आते हैं, जिन पर राहुल गांधी, सोनिया गांधी और राजीव गांधी की आलोचना की गई है। क्या शर्मिष्ठा मुखर्जी के साथ पी.चिदम्बरम की तस्वीर कांग्रेस आलाकमान सहज ढंग से लेंगे या इसमें छिपे संदेश को समझेंगे। ये वक्त सारे गम भुलाकर घूमने का कतई नहीं है, कांग्रेस और इंडिया को देश में छाए धुंधलेपन को किसी न किसी तरह दूर करना ही होगा।

पुराने आपराधिक कानूनों की विदाई

कानूनों में समय–समय पर बदलाव निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जिस समय संविधान लागू हुआ था उस समय और अब के भारत में जमीन–आसमान का फर्क है। इस फर्क के हिसाब से भी लोगों की जरूरतें बदली हैं। किसी भी देश का संविधान उसकी जरूरतों को पूरा करने लायक होना चाहिए। हमारे संविधान की यह खासियत है कि इसमें समय की जरूरत को देखते हुए कई बदलाव किए जा चुके हैं। अगर कानूनों में संशोधन नहीं किए जाते तो समान सामाजिक और आर्थिक सुधार कैसे सम्भव हो सकते थे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की कार्यप्रणाली अन्य प्रधानमंत्रियों की तुलना में काफी अलग रही है। वह कुछ नया करने की सोच रखते हैं और सिद्धांत पर चलते हैं। यही वजह है कि वर्ष 2014 में सत्ता सम्भालने के बाद से ही उन्होंने देश के पुराने और अप्रसांगिक हो चुके कानूनों को न केवल खत्म किया है बल्कि कई कानूनों में आवश्यक संशोधन भी किए हैं। 1500 कानूनों से ज्यादा कानूनों को खत्म किया जा चुका है, जिनमें से ज्यादातर कानून अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे थे। इसके पीछे मंशा लोगों को सहूलियत प्रदान करना है। सरकार ने 25 हजार से ज्यादा शर्तों को समाप्त किया है। जिनमें जाली नोट फैलाने और सरकारी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने को भी टेरर एक्ट में शामिल किया गया है। यह सब इस सिद्धांत पर आधारित है कि जहां जरूरत हो वहां सरकार का अभाव नहीं होना चाहिए लेकिन जहां जरूरत न हो वहां सरकार का प्रभाव भी नहीं होना चाहिए। पुराने कानून अंग्रेजों ने अपने हिसाब से बनाए थे जिनका लक्ष्य केवल दंड देना था लेकिन अब सरकार का उद्देश्य केवल दंड देना नहीं बल्कि न्याय देना है। अब इंडियन पीनल कोड (1860) क्रिमिनल प्रोसीजर कोड (1898) और इंडियन एविडेंस एक्ट (1872) में बने इन कानूनों को अलविदा कहकर कानूनी ढांचे में एक बड़े बदलाव की ओर सरकार ने कदम बढ़ा दिए हैं। इससे गुलामी की निशानियां तो समाप्त होंगी ही साथ ही न्याय देने की व्यवस्था भी पुख्ता होगी। इस संबंध में तीन विधेयकों को गृहमंत्री अमित शाह ने पिछले मानसून सत्र खत्म होने से पहले लोकसभा में पेश किया था जिन्हें स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा गया था। गृहमंत्री ने शीतकालीन सत्र में मंगलवार को आपराधिक कानूनों में जुड़े तीन विधेयकों को वापिस ले लिया और इनकी जगह नए विधेयक पेश कर दिए। इन मसौदा विधेयकों में संसद की स्टैंडिंग कमेटी के सुझावों को शामिल किया गया। एक विधेयक में आतंकी कृत्य की परिभाषा का दायरा बढ़ाया गया है। नए सिरे से पेश किए गए विधेयकों में आतंकवाद की परिभाषा समेत कम से कम पांच बदलाव किए गए हैं। भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता विधेयक में कई बदलावों के साथ–साथ आर्थिक सुरक्षा शब्द भी शाधमिल है।

भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) विधेयक, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) विधेयक, 2023 और भारतीय साक्ष्य (बीएस) विधेयक, 2023 को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), 1860, दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी),1898 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 का स्थान लेने के लिए लाया गया है। शाह ने मानसून सत्र के दौरान 11 अगस्त को सदन में ये विधेयक पेश किए थे। बाद में इन्हें गृह मामलों से संबंधित संसद की स्थायी समिति के पास भेज दिया गया था। विधेयक में धारा 73 में बदलाव किए गए हैं जिससे अदालत की ऐसी कार्यवाही प्रकाशित करना दंडनीय हो जाएगा जिसमें अदालत की अनुमति के बिना बलात्कार या इसी तरह के अपराधों के पीड़ितों की पहचान उजागर हो सकती है। धारा 73 में अब कहा गया है, 'जो कोई भी अदालत की पूर्व अनुमति के बिना धारा 72 में निर्दिष्ट अपराध के संबंध में अदालत के समक्ष किसी भी कार्यवाही के संबंध में किसी भी मामले को प्रिंट या प्रकाशित करेगा, उसे एक अवधि के लिए कारावास की सजा दी जाएगी। इसे दो साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।'

भारत के कानून में कई ऐसे शब्दों का जिक्र था जो आजादी से पहले के हैं, इनमें ब्रिटिश शासन की झलक थी जिसे अब निरस्त कर दिया गया है, करीब 475 जगह इनका इस्तेमाल होता था जो अब नहीं होगा। अब सबूतों में डिजिटल रिकॉर्ड्स को कानूनी वैधता दी गई है ताकि अदालतों में कागजों का ढेर नहीं दिया गया है। एफआईआर से लेकर केस डायरी तक को अब डिजिटल किया जाएगा, किसी भी केस का पूरा ट्रायल अब वीडियो कॉन्फ्रेंगिंग से किया जा सकता है। किसी भी मामले की पूरी कार्यवाही डिजिटल तौर पर की जा सकती है।

साह ने कहा कि किसी भी सर्च में अब वीडियोग्राफी जरूरी होगी, इसके बिना कोई भी चार्जशीट वैध नहीं होगी। हम फॉरेन्सिक साइंस को मजबूत कर रहे हैं, जिस भी मामले में 7 या उससे अधिक साल की सजा है उसमें फॉरेन्सिक रिपोर्ट आवश्यक होगी यानी यहां पर फॉरेन्सिक टीम का विजिट करना जरूरी होगा, हमने दिल्ली में सफल तरीके से लागू किया है। हमारा फोकस 2027 से पहले सभी कोर्ट को डिजिटल करने की कोशिश है। नए बिल के तहत जीरो एफआईआर को लागू करेंगे, इसके साथ ही ई–एफआईआर को जोड़ा जा रहा है। जीरो एफआईआर को 15 दिनों के भीतर संबंधित थाने में भेजना होगा, पुलिस अगर किसी भी व्यक्ति को हिरासत या गिरफ्तार करती है तो उसे लिखित में परिवार को सूचना देनी होगी। विपक्षी दल इन विधेयकों को फिर से स्थाई समिति को सौंपने की मांग कर रहा है, इस पर गृहमंत्री ने कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो ऐसा कर सकते हैं। जरूरत के अनुसार विधेयक में फेरबदल किया जा सकता है।

दबंगों ने आम रास्ते पर किया कब्जा,

एलडीए अधिकारियों से शिकायत के बाद भी नहीं मिल रहा न्याय,

लखनऊ। राजधानी की खूबसूरती बिगाड़ रहे अवैध निर्माण, अवैध निर्माण को रोकने में बुरी तरह विफल साबित हो रहे अभियंता और अधिकारी, प्रवर्तन जोन–7 के चौक क्षेत्र में मानकों के विपरीत कई व्यावसायिक व आवासीय अवैध निर्माण धड़ल्ले से जारी है। लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष इंद्रमणि त्रिपाठी अवैध निर्माण पर रोक लगाने के चाहे जितने दावे करलें परन्तु धरातल पर सब शून्य नजर आ रहे हैं। सच तो यह है की अवैध निर्माण करने वाले दबंगों के हौसले चरम पर हैं।

दबंग सरकारी जमीन और रास्ते पर कब्जा करने से भी नहीं डरते। और ना ही विकास प्राधिकरण के मानकों की परवाह कर रहे, एलडीए विभाग के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रहीं हैं। रास्ते की जमीन पर कब्जा कर अवैध इमारत तैयार हो रही है। मालूम हो कि चौक प्रवर्तन जोन–7 के राजा बाजार में स्थित भवन संख्या 231/54 बाग मक्का में दोनों मकान आमने–सामने स्थित है। बीच में लगभग 5 फीट चौड़ी गली है। लेकिन मकान नंबर 231/54 के मालिक आगा मोहम्मद हसन व 231/56 के मालिक ताहिर हसन द्वारा सरकारी रास्ते पर एक राय होकर छत डाल ली है। लगभग 2400 Sq-Ft भूमि पर उक्त अब तीसरी मंजिल का निर्माण बिना मानचित्र स्वीकृत के अवैध रूप से करा रहा है। शिकायतकर्ता रानी बेगम ने अवर अभियंता शशि भूषण मिश्र को बताया कि मेरा मकान गली में सबसे आखरी है। जिसमें जाने का मेरा एकमात्र रास्ता उक्त के घर के सामने से होकर ही निकलता है। दबंगई के बल पर चुप्पी सादे हुए हैं।

जबकि दबंगों ने रास्ते की जमीन पर कब्जा कर मानकों की धज्जियां उड़ाते हुए अवैध इमारत बनकर तैयार हो रही है। जोन–7 के सहायक अभियंता एवं अवर अभियंता का निर्माणकर्ताओं को संरक्षण प्राप्त होने के कारण क्षेत्र में धड़ल्ले से

सरकारी रास्ते को घेर कर अवैध निर्माण कर रहे हैं। अवैध रूप से दबंगों द्वारा अवैध निर्माण कराया जा रहा है। शिकायतकर्ता रानी बेगम ने दिनांक 26.11.2023 को मुख्यमंत्री पोर्टल के माध्यम से एलडीए में शिकायत दर्ज कराई थी। रास्ते पर हो रहे कब्जे को लेकर चौक थाने पर जाकर तहरीर भी दी थी। पूर्व में भी थाने पर पीड़ित कई प्रार्थना पत्र दे चुका है। अभी तक शिकायतकर्ता लगातार एलडीए एवं चौक थाने के चक्कर काट रहा है। लेकिन दबंगों के खिलाफ कोई करवाई नहीं हो रही है। पुलिस विभाग भी कई अवैध निर्माण चल रहें है। जबकि हाईकोर्ट के सख्त आदेश है कि सरकारी एवं रास्ते की जमीन पर कोई निर्माण नहीं हो सकता। जबरन निर्माण करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। वीसी के तमाम दावों पर अधिकारी और अभियंता पानी फेरते नजर आ रहे हैं। सहायक अभियंता क्षेत्र में नहीं रोक पा रहे अवैध निर्माण। इन जैसे तमाम अवैध निर्माण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेशों को ठेंगा ही नहीं मुंह चिढ़ाते नजर आ रहे हैं। विकास प्राधिकरण के नियम प्रभावी ना होकर अब तक सफेद हाथी साबित हुए।

यूपी शिक्षक भर्ती के बदले नियम, लिखित परीक्षा के 90 और इंटरव्यू के 10 प्रतिशत अंकों पर बनेगी मेरिट लिस्ट

लखनऊ। उत्तर–प्रदेश के शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की भर्ती के लिए विभिन्न आयोगों और चयन बोर्डों के स्थान पर एक ही संस्था को बनाए जाने के फैसले के बाद अब शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए शिक्षक भर्ती के नियमों में सरकार ने दलाव किया है। नए नियमों के मुताबिक लिखित परीक्षा के 90 और इंटरव्यू के 10 प्रतिशत को जोड़ कर मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। पारदर्शिता के लिए साक्षात्कार में न्यूनतम 40 प्रतिशत व अधिकतम 90 प्रतिशत तक अंक दिए जा सकेंगे। अब शैक्षिक गुणांक में हाईस्कूल इंटरमीडिएट स्नातक और बीएड व बीटीसी के अंक नहीं जोड़े जाएंगे। जहां साक्षात्कार नहीं होगा वहां लिखित परीक्षा के अंकों के आधार पर ही भर्ती की जाएगी। परीक्षा दो घंटे की होगी और इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा ओएमआर शीट पर कराई जाएगी। अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में भर्ती के लिए एक अलग विशेषज्ञ पैनल भी होगा जो पूरी भर्ती प्रक्रिया पर अपनी नजर रखेगा। उप्र शिक्षा सेवा चयन आयोग के एक अध्यक्ष व 12 सदस्यों के चयन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में स्क्रीङ्क्षनग कमेटी बनाई गई है। अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा इसके सचिव बनाए गए हैं। इसी तरह अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक, माध्यमिक शिक्षा व बेसिक शिक्षा इसके सदस्य होंगे। विज्ञापन के 25 दिनों के भीतर यह इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगेंगे। अध्यक्ष पद के लिए पांच अभ्यर्थियों व सदस्यों के लिए प्रत्येक पद पर तीन गुणा अभ्यर्थियों के नाम की सूची तैयार करेगी। अंतिम चयनितों की सूची मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद जारी की जाएगी। आयोग के अध्यक्ष पद के लिए प्रमुख सचिव स्तर का आइएएस अधिकारी, किसी विश्वविद्यालय का कुलपति या पूर्व कुलपति, किसी विश्वविद्यालय का प्रोफेसर जिसका कम से कम 10 वर्ष का अनुभव हो और तीन वर्ष का प्रशासनिक अनुभव हो। वहीं सदस्य के रूप में सचिव स्तर के आइएएस अधिकारी, संयुक्त निदेशक उच्च शिक्षा, संयुक्त निदेशक माध्यमिक शिक्षा, संयुक्त निदेशक बेसिक शिक्षा स्तर का अधिकारी, अपर निदेशक व्यावसायिक शिक्षा, एक सदस्य न्यायिक सेवा यानी जिला न्यायाधीश स्तर और वहीं छह सदस्य ऐसे होंगे जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया हो। बता दें कि पूर्व की शिक्षक भर्ती में शैक्षिक गुणांक हाईस्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक और बीएड व बीटीसी के अंक जोड़े जाते थे। वहीं डिग्री कालेजों में प्रचार्यों की भर्ती में लिखित परीक्षा, साक्षात्कार और शैक्षिक प्रदर्शन सूचक (एपीआइ) के अंक जोड़कर चयनित अभ्यर्थियों की मेरिट तैयार की जाती रही है।

वोट हमारा सामाजिक व राजनीतिक अधिकार है : मोहम्मद अफाक

लखनऊ। हाजी मुहम्मद फहीम सिद्दीकी के नेतृत्व में शहर के विभिन्न क्षेत्रों में राजनीतिक और सामाजिक संगठनों द्वारा मतदान जागरूकता अभियान चलाया गया। उन्होंने मतदान के बारे में बताते हुए कहा कि आज आधार कार्ड और पेन कार्ड उपयोग सांसारिक लाभों के लिए किया जाता है।इन कार्ड पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है, जबकि इस देश में रहने वाले लोगों का असली अधिकार वोट देना है। और कोई भी व्यक्ति तभी वोट कर सकता है जब उसका वोटर कार्ड बना हो और उसका नाम वोटर लिस्ट में हो. उन्होंने कहा कि जनता के बीच वोट के महत्व पर जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए ताकि लोग लोकतंत्र में मतदान के महत्व को जान सकें। मुहम्मद अफाक ने कहा कि वोट हमारा सामाजिक एवं राजनीतिक अधिकार है, इसका प्रयोग बहुत सोच समझकर करना चाहिए। यदि हम वोट देने का अपना अधिकार वापस लेते हैं या त्याग देते हैं, तो इसका दुरुपयोग होगा और पूरे देश को नुकसान होगा। हमारे पास अपनी पसंद के उम्मीदवार को सफल बनाने का मौका है. हमें वोट की वास्तविकता को समझना चाहिए और धर्मनिरपेक्ष पार्टी और धर्मनिरपेक्ष विचारधारा वाले उम्मीदवार को सफल बनाने के लिए इसके महत्व का आकलन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सच्चे और देश हित में काम करने वाले उम्मीदवारों को सफल बनाने के लिए लोगों का मार्गदर्शन करना हमारा सामूहिक कर्तव्य है। यह कार्य इतना व्यापक है कि इसमें कई संगठनों को भाग लेना होगा। अंत में उन्होंने संगठनों से अपील की कि वे राष्ट्रीय जागरूकता अभियान में हमारे साथ जुड़ें या अपने स्तर पर जनता को प्रोवोट की वास्तविकता से अवगत कराएं. नगर अधिकार परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष रफी अहमद, शहजादे मंसूर अहमद ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि इस देश में आपको पूरा अधिकार है कि आप जहां भी हों अपना वोटर कार्ड ऑनलाइन बनवा सकते हैं। इसलिए अगर कोई भाई अपने शहर से दूसरे शहर में कोई बिजनेस करता है तो उसे यह नहीं सोचना चाहिए कि जब हम घर जाएंगे तो वोटर कार्ड बनवालेंगे ।आप जहां भी हों अपना वोटर कार्ड जरूर बनवाएं। इस मौके पर इरशाद अहमद सिद्दीकी, बहन फरीदा, रोशन जहां समेत कई संगठनों के नेता शामिल हुए।

नैनीताल बैंक शाखा नादान महल का उदघाटन

बैंक समाज की विकास की रीढ़ है : बृजेश पाठक

लखनऊ। नैनीताल बैंक की नवीनीकृत शाखा के नए परिसर का उदघाटन गुरुवार 14 दिसम्बर को प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने किया। बाद में उन्होंने कहा कि बैंक समाज की विकास की रीढ़ हैं। तुलसीदास मार्ग, तुरियागंज में स्थित बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी निखिल मोहन ने बैंक की महत्वाकांक्षी योजनाओं से ग्राहकों सहित अन्य उपस्थित विशिष्ट जनों को रूबरू करवाया। उन्होंने बताया कि बैंक बहुमुखी विकास के लिए औद्योगिक और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को सस्ती दरों पर ऋण सुविधाएं दे रहा है। नैनीताल बैंक लिमिटेड जिसे अब नैनीताल बैंक के नाम से जाना जाता है की स्थापना भारत रत्न देश के चौथे गृह मंत्री और उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत ने की थी। वर्तमान में नैनीताल बैंक की भारत में 166 से अधिक शाखाएँ हैं। यह पर्सनल बैंकिंग, बिजनेस बैंकिंग, ग्रामीण और कृषि बैंकिंग के अलावा ऑनलाइन सुविधाएं भी प्रदान करता है। नैनीताल बैंक लिमिटेड भारतीय रिजर्व बैंक, भारत के केंद्रीय बैंक के साथ अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के रूप में पंजीकृत है। इस अवसर पर क्षेत्रीय प्रबंधक सनी मेहरा, उप क्षेत्रीय प्रबंधक अभिषेक गोयल, परिसर विभाग के वरिष्ठ प्रबंधक, प्रदीप सिन्हा, वरिष्ठ प्रबंधक शरद दुबे एवं सुधीर सिंह सिंह, नादान महल शाखा के प्रबंधक कन्हैया कुमार मल सहित ग्राहक और बैंक के अनेक अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे।

हाईवे किनारे होटल पर पुलिस का छापा, मिले स्टूडेंट

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के जनपद बाराबंकी के सफदरगंज थाना क्षेत्रान्तर्गत लखनऊ–अयोध्या नेशनल हाईवे पर होटल में भारी पुलिस बल ने छापा मारा। होटल की तलाशी में अंदर 10 जोड़े मिले। पूछताछ में सभी डिग्री और मैनेजमेंट कॉलेजों के छात्र–छात्राएं निकले, जो कॉलेज टाइम में मौजूद थे। पुलिस ने काउंसलरों को बुलाकर सभी को समझाया और अभिभावकों को भी आगाह किया। पुलिस ने होटल में कोई अवांछनीय गतिविधि नहीं होने के कड़े निर्देश दिए हैं। सफदरगंज थाना क्षेत्र में बरियारपुर गांव के पास हाईवे पर गीता होटल एवं रेस्टोरेंट है। पुलिस अधिकारियों को शिकायत मिल रही थी कि इसमें देह व्यापार होता है। एसपी के निर्देश पर सीओ सदर सुमित त्रिपाठी, महिला थानाध्यक्ष, एनजीओ की महिला काउंसलरों की टीम ने बुधवार दोपहर अचानक होटल में छापा मारा। पुलिस ने होटल के कमरों को खुलवाया तो करीब 10 कपल मिले। होटल के रजिस्टर पर सभी का नाम, पता अंकित था। पता लगा कि सभी युवक व युवतियां 18 से 21 साल की उम्र के हैं और छात्र–छात्राएं हैं। इन लोगों ने होटल में अलग–अलग कमरा बुक कराया था। पुलिस ने कमरों के अंदर इस बात की ताकीद की कि कहीं कोई वीडियो रिकॉर्डिंग तो नहीं हो रही। पुलिस सभी को साथ ले गई और काउंसलरों के माध्यम से समझाया गया। उन्हें बताया कि गया कि ऐसी जगहों पर जाने के क्या नुकसान हो सकते हैं। एसपी दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि सभी बालिग हैं इसलिए छोड़ दिया गया है। होटल व ढाबों में ऐसी गतिविधियों को लेकर पुलिस लगातार अभियान चलाएगी। सीओ सिटी के कार्यालय में हाइवे किनारे स्थित होटल, ढाबों और रेस्टोरेंट मालिकों व प्रबंधकों के साथ पुलिस ने बैठक की। सीओ डॉ. बीनू सिंह ने सभी से सुरक्षा व यातायात व्यवस्था को लेकर कई निर्देश जारी किए। सीओ ने कहा कि होटलों–ढाबों के बाहर सड़क पर वाहनों को खड़ा किया जा रहा है। इसलिए पार्किंग की समुचित व्यवस्था कर ली जाए। सुरक्षा की दृष्टि से पर्याप्त कैमरे लगाएं ताकि वाहन की नंबर प्लेट पढ़ी जा सके।

शिक्षक भर्ती नियम-शर्तें:90 नंबर की लिखित परीक्षा और 10 का इंटरव्यू

तीन साल में पूरी करानी होंगी भर्तियां

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती के लिए सरकार ने एक आयोग बनाने का निर्णय लिया था। सरकार ने आयोग के गठन के लिए निर्देश दिए थे। सरकार के आदेश के बाद उच्च शिक्षा विभाग में आयोग के गठन के साथ ही शिक्षक भर्ती के लिए प्रक्रिया क्या होगी इसकी अधिसूचना बुधवार देर रात को जारी कर दी।इसके तहत प्रदेश के उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा, अनुदेशक व सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक कॉलेजों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग की अधिसूचना जारी कर दी गई। अधिसूचना में आयोग में अध्यक्ष सदस्यों के चयन, अधिकारी की योग्यता और शिक्षक की भर्ती प्रक्रिया के लिए आयोजित होने वाली परीक्षा व इंटरव्यू की विस्तृत जानकारी दी है। अधिसूचना में कहा गया कि 3 साल के अंदर विज्ञापित पदों के सापेक्ष चयन प्रक्रिया पूरी नहीं होती है तो आयोग इस विज्ञापन को रद्द कर सकता है। आयोग फिर से नए सिरे से विज्ञापन जारी करेगा। अल्पसंख्यक संस्थानों में अध्यापकों के चयन के लिए विज्ञापन के लिए पदों की सूचना अलग से जारी की जाएगी। अधिसूचना के अनुसार आयोग विभिन्न स्तर पर शिक्षकों की भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया आयोजित कर सकता है। इसमें अध्यापक व अनुदेशक की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन कराया जाएगा। लिखित परीक्षा 2 घंटे की वस्तुनिष्ठ आधार पर होगी। अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा के लिए 90 प्रतिशत नंबर दिए जाएंगे जबकि 10 फीसदी नंबर इंटरव्यू के होंगे ।जहां साक्षात्कार नहीं होगा वह लिखित परीक्षा के ही पूरे नंबर जोड़े जाएंगे और पूर्णांक पदों के सापेक्ष तीन से पांच गुणा लोगों को आगे के लिए बुलाया जाएगा। प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा एमपी अग्रवाल ने नियमावली जारी करते हुए आयोग का अध्यक्ष प्रमुख सचिव स्तर के आईएएस अधिकारी को बनाया जाएगा। आयोग में किसी

का निर्धारण आयोग करेगा।लिखित परीक्षा जिला मुख्यालय पर होगी। अधिसूचना के अनुसार बेसिक विद्यालयों में शिक्षकों के चयन के लिए लिखित परीक्षा और शैक्षणिक गुणांक की वर्तमान व्यवस्था में भी बदलाव किया जा सकता है। अब इनका चयन या तो सीधे लिखित परीक्षा या लिखित परीक्षा व इंटरव्यू के आधार पर होगा। स्नातक व परास्नातक कॉलेज में प्राचार्य पद के लिए लिखित परीक्षा व एपीआई के आधार पर होगा। लिखित परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों से खाली भी विश्वविद्यालय के कुलपति, वरिष्ठ प्रोफेसर जो 10 साल का अनुभव, 3 साल का प्रशासनिक अनुभव रखता हो वह शामिल होगा। वही सदस्यों में सचिव स्तर के आईएएस अधिकारी उसे शिक्षा के संयुक्त निदेशक संयुक्त निदेशक बेसिक या माध्यमिक शिक्षा, न्यायक सेवा से जुड़े एक सदस्य, 6 सदस्य शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान करने वाले शामिल होंगे जबकि चयन प्रक्रिया में साक्षात्कार बोर्ड में एक विशेषज्ञ प्रतिनिधि को अतिरिक्त रखा जाएगा।

जिले में 3 दिवसीय मेले के आयोजन की तैयारी पूरी, हर साल लाखों लोग होते हैं शामिल

बांदा। मौनी धाम में 15,16 और 17 दिसंबर को आयोजित होने वाले विशाल मेला में भंडारा की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। साफ–सफाई व्यवस्था में सफाई कर्मी जुटे हुए हैं और मौनी धाम सहित प्रसाद प्रांगण को सजाने संवारने और रंगाई–पुताई के काम को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। मौनी धाम में विगत साल की भांति इस साल 15 दिसंबर से लेकर 17 दिसंबर तक विशाल भंडारे का आयोजन अवधूत महाराज द्वारा संपन्न कराया जाएगा। भंडारा और मेले की तैयारियों के लिए श्रमदानी व प्रशासनिक अमला लगा हुआ है। पर्यटन स्थल रामलीला और नाटक मंचन प्रांगण व मधुबन की साफ–सफाई के लिए सफाई कर्मी तैनात किए गए हैं। पर्यटक स्थल में 15 दिसंबर से खेलकूद की प्रतियोगिता होगी। रामलीला और नाटक प्रांगण में देश–प्रदेश के प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा दिन में नाटक एवं रात में रामलीला का मंचन करेंगे। भंडारा प्रांगण की साफ–सफाई और रंगाई–पुताई का कार्य अन्तिम चरण पर तेजी से चल रहा है, जहां एक साथ 11 हजार श्रद्धालुओं को पंगत में बैठाकर खिलाने का इंतजाम रहता है। मधुबन में देश देशांतर के आश्रम से आने वाले साधु सन्यासियों के ठहरने के लिए व्यवस्था की जा रही है। स्टाल लगने शुरू हो गये है क्षेत्र और अन्य जिलों की दुकानें लगाना शुरू हो गई है। श्रमदानी सेवकों ने तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सामग्री आना शुरू है और दूर–दूर से श्रमदानियों ने डेरा डाला दिया है। मौनी धाम में 108 वर्ष सीता–राम संकीर्तन दिन रात रामधुन अनवरत जारी रहती है, जिसमें आसपास के गांव के श्रद्धालु भक्त आते है, जिन्हें स्वामी अवधूत महाराज जी का सानिध्य प्राप्त रहता है। स्वामी जी के बैराग्य उत्पन्न होने पर से ही संकीर्तन का शुभारंभ किया गया। तब से अनवरत रामधुन संकीर्तन जारी है। भंडारे व मेले में आकर्षण का केन्द्र भगवान हनुमान की लेटी प्रतिमा 110 फीट और शंकर जी की प्रतिमा 85 फीट की ऊंचाई पर और नंदी जी प्रतिमा आर्कषण का केन्द्र है।

641 बच्चियों ने दिखाई प्रतिभा,मंत्री बेबी रानी मौर्य और प्रतिभा शुक्ला हुई शामिल

बांदा। नारी शक्ति समागम के तहत बच्चियों की खेल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है। इसमें बतौर मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य और बतौर विशिष्ट अतिथि प्रतिभा शुक्ला शामिल हुईं। आयोजन में चित्रकूट धाम मंडल के बांदा, चित्रकूट, महोबा, हमीरपुर जनपद से कुल 641 बच्चियों ने प्रतिभाग किया है और अपने हुनर का प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि नारी शक्ति समागम के तहत चित्रकूट धाम मंडल के मंडल मुख्यालय बांदा में बच्चियों के खेल प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया, जिसमें बांदा, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट सभी चारों जिलों से कुल 641 बच्चियों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया है। खेलो इंडिया के तहत प्रधानमंत्री द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान में मंडल के चारों जिले के 641 बच्चियों ने प्रतिभाग किया है। खो–खो, शूटिंग, बैडमिंटन, वालीबॉल, कबड्डी, एथिलेटिक्स समेत विभिन्न खेलों का आयोजन करवाया गया है।

बतौर मुख्य अतिथि आयोजन में शामिल हुईं कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य ने बताया कि प्रधानमंत्री के द्वारा खेलो इंडिया के तहत जिस तरह से बच्चों को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है उसी के तहत आज चित्रकूट मंडल में जिलाधिकारी की सराहनीय पहल के चलते आयोजन करवाए गए हैं, जिसमें गांव की बच्चियां भी शामिल हैं। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार की राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने कहा कि बच्चियों को आगे बढ़ाने के लिए सराहनीय प्रयास किया जा रहा है। कैसे बच्चियों को आत्मनिर्भर बनाकर आगे बढ़ाया जाए उसको लेकर के यह अच्छा आयोजन था। बेटियों के लिए ऐसे आयोजन होते रहने चाहिए। जब बेटी आगे बढ़ेगी तब भारत आगे बढ़ेगा। जिलाधिकारी बांदा दुर्गा शक्ति नागपाल के लिए भी दोनों ही मंत्रियों ने कहा कि अच्छा कैंपेन चला करके चारों मंडल से बच्चियों को लाया गया है और खेलकूद की प्रतियोगिता का अच्छा आयोजन किया गया है। वहीं जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल ने बताया कि बांदा चित्रकूट महोबा और हमीरपुर कल चारों जनपद से 641 बच्चियों ने प्रतिभाग किया है। मंत्रीगणों ने आकर के बच्चों का हौसला बढ़ाया है। विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है।

आर्मी अफसर के बेटे को रौंद कर भाग निकला रोडवेज बस चालक, पत्नी और बेटी घायल

लखनऊ। पीजीआई थाना क्षेत्रान्तर्गत अपने मासूम बेटे अभिमन्यु और बेटी राखी को स्कूल छोड़ने जा रही महिला सपना सिंह की स्कूटी में एक अज्ञात बस चालक ने टक्कर मार दी। स्कूटी में टक्कर लगने के बाद दोनों बच्चे और सपना सड़क पर गिर पड़े। भागने

के प्रयास में बस चालक मासूम बेटे को रौंदते हुए भाग निकला। हादसे में महिला और उसकी बेटी भी गंभीर रूप से घायल हो गई ।राहगीरों की मदद से सभी को आननफानन पीजीआई के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया,जहां बेटे की मौत हो गई ।बेटे अभिमन्यु के पिता हरिकरण सिंह आर्मी अफसर हैं जो इस वक्त राजस्थान में तैनात हैं। लखनऊ के पीजीआई थाना क्षेत्र अंतर्गत सी–12 साहू कॉलोनी एकतानगर निवासी हारिकरण सिंह आर्मी में हैं ।वे राजस्थान में तैनात हैं। हरिकरण सिंह की पत्नी सपना सिंह अपने दो बच्चों के साथ लखनऊ में ही रहती हैं। रोज की तरह गुरुवार सुबह आठ बजे सपना सिंह बेटे अभिमन्यु (12) और बेटी राखी को स्कूटी से एलपीएस स्कूल छोड़ने जा रही थीं ।सभा खेड़ा मोड़ पर पहुंचते पर एक रोडवेज बस ने स्कूटी में टक्कर मार दी। बस की टक्कर से स्कूटी सवार सपना अपने बेटे और बेटी के साथ सड़क पर गिर पड़ीं। बस चालक मासूम को रौंदते हुए मौके से बस लेकर भाग निकला। मासूम की मौके पर ही मौत हो गई ।हादसा देख राहगीरों ने किसी तरह मासूम और घायल मां–बेटी को पीजीआई ट्रामा सेंटर पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने अभिमन्यु को मृत घोषित कर दिया। गंभीर रूप से घायल मां–बेटी इलाज चल रहा है। अभिमन्यु कक्षा 6 में पढ़ता था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है ।डीसीपी पूर्वी आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि गुरुवार सुबह स्कूटी से बच्चों अभिमन्यु व राखी को एलपीएस स्कूल छोड़ने जा रही महिला की स्कूटी में रोडवेज बस चालक ने टक्कर मार दी थी।

राजकीय आईटीआई में कैंपस ड्राइव 16 को

लखनऊ। आईटीआई अलीगंज के प्रधानाचार्य राज कुमार यादव ने बताया कि 16 दिसम्बर को राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अलीगंज लखनऊ में हिन्दूस्तान यूनीलीवर लिमिटेड, सूमेरपुर, हमीरपुर, उत्तर प्रदेश के कैम्पस ड्राइव का आयोजन किया जा रहा है ।ट्रेनिंग काउंसिलिंग एण्ड प्लेसमेन्ट आफिसर एम ए खाँ ने बताया कि कम्पनी में परमानेन्ट जॉब के अवसर है जिसमें शैक्षिक योग्यता आईटीआई के फिटर, टर्नर, मशीनिष्ट, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रानिक मैकेनिक, इन्ट्रूमेन्ट मैकेनिक एवं डिप्लोमा इलेक्ट्रीकल, मैकेनिक के उत्तीर्ण किया हो वे ही प्रतिभाग कर सकते है, 1 वर्ष का अनुभव प्राप्त किया हो या अप्रेन्टिसशिप या सीआईटीएस किया हो वे पात्र होंगे। आयुसीमा 20 से 30 वर्ष हो। वेतन 10 हजार से 12 हजार रुपये प्रतिमाह एवं अन्य सुविधाएं कम्पनी द्वारा दी जायेगी। मेले में केवल महिला अभ्यर्थी प्रतिभाग कर सकते है ।200 पदों पर चयन किया जायेगा ।इच्छूक अभ्यर्थी 16 दिसम्बर को अपने बायोडाटा के साथ समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्रों को संलग्न करते हुए प्रातः 09 बजे राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होकर रोजगार प्राप्त कर सकते है।

सेना दिवस 2024 पर लखनऊ भव्य सैन्य परेड के लिए तैयार

लखनऊ। जनवरी 2024 में लखनऊ, पहली बार, भव्य आर्मी डे परेड की मे जबानी करेगा। भारतीय सेना की मध्य कमान, जिसे सूर्या कमान के नाम से भी जाना जाता है, 15 जनवरी, 2024 को लखनऊ छावनी स्थित 11 गोरखा राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर में 76 वीं सेना दिवस परेड का आयोजन करेगी। आजादी के बाद यह दूसरी बार है जब सेना दिवस दिल्ली के बाहर आयोजित किया जा रहा है। भारतीय सेना की रेजिमेंटों से हमारे वीर सैनिकों की मार्चिंग टुकड़ियां परेड में भाग लेंगे, जिनमें गढ़वाल राइफल्स, जाटरेजिमेंट, बंगाल इंजीनियर्स, सिखलाइट इन्फैंट्री, आर्मी एयर डिफेंस और पैरा ट्रूपर्स के साथ अन्य सैनिक भी शामिल हैं। परेड के दौरान भारतीय सेना के वीरता पुरस्कार विजेताओं को भी सम्मानित किया जाएगा। सेना दिवस समारोह के हिस्से के रूप में, लखनऊ छावनी के सूर्या खेल परिसर में एक सैन्य प्रदर्शन शौर्य संध्या भी आयोजित किया जाएगा। लखनऊ के लोगों को भारतीय सेना के उपकरणों और युद्ध अभ्यास का प्रत्यक्ष अनुभव मिलेगा जो हमारे सैनिकों के कौशल और वीरता को प्रदर्शित करेगा। भारतीय वायु सेना की हवाई एसेट भी इस कार्यक्रम में फ्लाई पास्ट मे शामिल होंगी, साथ ही भारतीय सेना की मोटरसाइकिल टीम द्वारा डेयर डेविल प्रदर्शन भी किया जाएगा। इस कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिक और सैन्य गणमान्य व्यक्तियों के भाग लेने की अपेक्षा है। इस भव्य आयोजन के लिए सूर्या कमान में तैयारियां जो रोंप रहें। इस ऐतिहासिक अवसर को चिह्नित करने के लिए लखनऊ में ष्नोयोर आर्मीष फेस्टिवल, मिलिट्री बैंड कॉन्सर्ट, रक्तदान शिविर, वृक्षारोपण अभियान और अन्य गतिविधियां भी सूर्या कमान में आयोजित की जा रही हैं। ऐतिहासिक रूप से आर्मी डे को चिह्नित करने के लिए नई दिल्ली में परेड आयोजित की जाती थी। सेना दिवस परेड 2024 की मेजबानी करने का अवसर मिलना सूर्या कमान और लखनऊ के लिए गर्व और सम्मान की बात है। यह वास्तव में इस क्षेत्र के लोगों की गौरवपूर्ण सैन्य विरासत और वीरता का एक प्रमाण है।

इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के परदेश सचिव मुहम्मद मुहम्मद ने मुस्लिम लीग से दिया इस्तीफा

लखनऊ। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के परदेश सचिव मुहम्मद अहमद ने मुस्लिम लीग से इस्तीफा देते हुए कहा कि मैं कुछ महीने पहले ही मुस्लिम लीग में शामिल हुआ था, लेकिन परदेश अध्यक्ष डॉ. मतीन ने निर्देशों के अंबार लगाने शुरू कर दिए और हमें सलाह दी की किसी भी परोगरम में पार्टी की रूप से न जायें। हद तो तब हो गई जब मैंने ग्रुप में मुस्लिम लीग के नाम से पोस्टर लगा दिया। इस पोस्टर को तुरंत ग्रुप से हटा ने की बात काही गई । क्योंकि इस ग्रुप में मैं अंजुमनों और वक्फ बोर्ड में होने वाले भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा होता था और मैं उनकी तस्वीर और खबरें ग्रुप में डालता था, तो इससे किसी अविश्वासी को ठेस पहुंची और उसने डॉ. मतीन के माध्यम से हम पर उस पोस्टर को हटवा ने का दबाव डाला। इसीलिए मैंने 13 दिसंबर 2023 को पोस्टर सहित पार्टी से इस्तीफा दे दिया। अब मेरा मुस्लिम लीग से कोई लेना–देना नहीं है।

पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी के चलते यूपी का गिरा पारा, इन इलाकों में घने कोहरे की संभावना

लखनऊ। यूपी और पंजाब समेत कई राज्यों में कड़ाके की ठंड शुरू हो गई है। जहां पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी के चलते शीत लहर भी चल रही है। जिसके चलते मैदानी इलाकों में पारा गिरने लगा है। यूपी की बात करें तो यहां तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। यहां पर मिनिमम और मैक्सिमम टेप्रेचर में कमी आने से लोगों को कड़ाके की ठंडक का अनुभव होने लगा है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ, मुजफ्फरनगर, नोएडा में तापमान में लगातार गिरावट देखी जा रही है। बीते दिन यानी गुरुवार को सबसे कम न्यूनतम तापमान मुजफ्फरनगर में दर्ज हुआ जहां पर इस सीजन की सबसे ठंडी रात गुजरी। दिसंबर की शुरुआत के साथ ही यूपी में लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। दिन में धूप निकल रही है तो वहीं शाम में सर्दी बढ़ने लगती हैं। 14 दिसंबर यानी आज पश्चिमी और पूर्वी यूपी के भाग में मौसम के शुष्क के आसार हैं। इस दौरान इन जिलों में अलग–अलग जगहों पर घने कोहरे की चादर छाए रहने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की माने तो अगले पांच दिनों तक यूपी में अधिकतम व न्यूनतम टेंप्रेचर में कोई विशेष बदलाव के आसार नहीं हैं। 15, 16 और 17,18 दिसंबर के समयावधि में मौसम के शुष्क रहने के अनुमान हैं। गुरुवार यानी आज की सुबह पश्चिमी यूपी में उत्तरी भागों में कुछ जगहों व पूर्वी यूपी के तराई इलाकों में अलग–अलग जगह पर घना कोहरा होने के आसार हैं। आज सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत, बहराइच, श्रावस्ती और बलरामपुर में सुबह के समय कोहरा छाया रहा।

ठेकेदार के घर से लाखों की जेवर,नकदी चोरी

बांदा। रेलवे ठेकेदार के मकान में चोरों ने धावा बोलकर 13 लाख रुपये के जेवर व 95 हजार रुपये नगद में हाथ साफ कर दिया। चोर जेवर व रुपये से भरा बक्सा उठा ले गए। खाली बक्सा पड़ोसी की मकान की छत में पड़ा मिला। घटना के समय पूरा परिवार गहरी नींद में सो रहा था। सुबह गृह स्वामिनी की नींद खुलने पर चोरी की जानकारी हुई। पति–पत्नी ने गांव से कोतवाली आकर तहरीर दी है। पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया। तहरीर के आधार पर अज्ञात पर चोरी की रिपोर्ट दर्ज की गई है। शहर कोतवाली क्षेत्र के डिंगवाही गांव निवासी योगेंद्र सिंह यादव रेलवे में ठेकेदारी करते हैं। बुधवार की रात वह अपनी पत्नी अंजना देवी के साथ कमरे में सो रहे थे। उनके बगल वाले कमरे में उनका छोटा भाई सो रहा था। रात में किसी समय कुछ चोर उनके मकान में छत के रास्ते से मकान के अंदर घुस गए। जिस कमरे में पति–पत्नी सो रहे थे उस कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। चोरों ने कमरे में घुसकर जेवर व रुपयों से भरा बक्सा पार कर दिया। सुबह होने पर अंजना की नींद खुली तो कमरे से बक्सा नदारद मिला। उन्होंने जानकारी पति योगेंद्र को दी। आस पड़ोस में चोरी की चर्चा की गई तो पड़ोसी होरीलाल साहू के मकान की छत में खाली बक्सा पड़ा मिला। योगेंद्र ने बताया कि बक्से में करीब 13 लाख रुपये के जेवर और 60 हजार रुपये नकद रखे थे। इसके अलावा गोलक में 35 हजार रुपये रखे थे। वह भी चोर ले गए। दंपति ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना किया है। शहर कोतवाल अनूप दुबे ने बताया कि सूचना पर उन्होंने मकान का मौका मुआयना किया है। चोरों के छत के रास्ते मकान में दाखिल होना प्रतीत हो रहा है।

फारेस्ट गार्ड भर्ती में अभ्यर्थियों ने लगाया धांधली का आरोप,

अभ्यर्थियों ने मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट पर उठाए सवाल, महिला अभ्यर्थी को टीवी का मरीज बताकर किया अनिफट

बस्ती। जिले में फारेस्ट गार्ड भर्ती के लिए आवेदन किए हुए अभ्यर्थियों ने भर्ती प्रक्रिया में धांधली किए जाने का आरोप लगाया है, यूआईपी कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे अभ्यर्थियों का यह कहना था कि उन्हें पैसे के चक्कर में मेडिकल अनफिट कर दिया गया है। इसी बीच एक महिला अभ्यर्थी डीएम कार्यालय पर पहुंच गई और उसने डीएम को बताया कि उसे मेडिकल बोर्ड बस्ती में अनफिट कर दिया गया था, जिसके बाद उसने सभी जांच सीएमओ संतकबीरनगर से कराई तो उसमें वह पूरी तरह से फिट पाई गई। बहुत से ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्हें इसीजी रिपोर्ट के आधार पर अनफिट कर दिया गया था। बृहस्पतिवार को काफी संख्या में यूआईपी केंद्र के बाहर पोस्ट गार्ड अभ्यर्थियों का जमावड़ा लगा हुआ था, अभ्यर्थी आकाश कुमार ने बताया कि 2019 में फारेस्ट गार्ड की भर्ती निकाली गई थी, 2022 में परीक्षा हुई, जिसमें उन्होने 25 किलो मीटर की रनिंग निकाला, बताया कि 11 दिसंबर को जब मेडिकल हुआ तो 17 अभ्यर्थियों को ईसीजी और पैर में दिक्कत दिखाकर बाहर कर दिया गया था। बताया कि पूरे 18 मंडल में भर्ती प्रक्रिया चल रही है, 17 मंडल में कुल मिलाकर 10 से 12 लोग फेल हुए हैं, बाकी इसी मंडल में पहले दिन 17 बच्चे फेल हुए 12 दिसबर को 33 में से 27 बच्चों को फेल किया गया, जब डीएफओ ने इंटरफेयर किया तो ईसीजी वालो को नार्मल कराया गया। इसके बावजूद पैर में व आंखों में दिक्कत दिखाकर नौ लड़कों को बाहर किया गया था। बताया कि जन बच्चों को बाहर गिया गया था, ईसीजी में तो नर्माल सबका आया है, उसके बावजूद बाहर किया गया है, जो बच्चे पैर में बाहर हुए हैं। उन्हें डॉक्टर खुद बोल रहे हैं कि आप लोग सही है गलती से हो गया है। दोनों डॉक्टर स्वीकार रहे हैं कि यह गलती से हुआ है। महिला अभ्यर्थी नेहा ने कहा कि यहां गलत तरीके से मेडिकल हुआ है, बच्चों को गलत तरीके से अनफिट किया गया है, इसी लिए हम लोग यहां धरने पर हैं। बताती है कि उन्हें टीवी का मरीज घोषित कर दिया गया, जो कि वो हैं नहीं। अगर वो टीवी की मरीज होती तो चलना भी मुश्किल रहता उनके लिए। बताया कि इसीलिए उन्होने अपना सिटिसकैन करवा लिया, तीन सर्जन का साइन भी करवा लिया सीएमओ संतकबीरनगर से भी दिखावा लिया। बताती हैं कि सीएमओ ने बोला कि सब नार्मल है। इसे लेकर वह डीएम बस्ती व एडी हेल्थ से मिलकर शिकायत भी की है। एडी हेल्थ डॉक्टर आरएस दुबे ने बताया कि कुछ बच्चे आए थे, इसमें मुख्य चिकित्साधिकारी के स्तर से मेडिकल टीम गठित की गई थी, पिछले दो दिनों से हो रहा है, आज उसका आखिरी दिन है। कहा कि बच्चे आए थे और उन्होने मुझे भी कहा वो लिए फिट हैं और उनको अनफिट घोषित कर दिया गया है। कोई व्यक्ति फिट है या नहीं है, यहा डिसाइड करना मेडिकल बोर्ड का काम है और मेडिकल बोर्ड अपना काम कर रही है। मैंने मुख्य चिकित्साधिकारी से वार्ता की है और उन्हें निर्देश दिया है यदि उनकी शिकायत जायज हो तो उसपर जांच कर लें और आवश्यक कार्यवाई करें।

होटल मैरियट में 11 दिवसीय दावत-ए-वाजवान कश्मीरी फूड फेस्टिवल शुरू

लखनऊ। गोमती नगर के विभूति खंड स्थित होटल फेयरफील्ड बाई मैरियट में गुरुवार से 11 दिवसीय दावत–ए–वाजवान कश्मीरी फूड फेस्टिवल की शुरूआत हुई। जनरल मैनेजर सचिन मल्होत्रा ने बताया कि होटल फेयरफील्ड बाई मैरियट हमेशा अपने मेहमानों के लिए कुछ अलग स्वाद लेकर आता है। जिसके मद्देनजर इस महीने 14 से 24 दिसंबर तक कश्मीरी फूड फेस्टिवल की शुरुआत की गई। सचिन मल्होत्रा का कहना है कि लोगो के बठने के लिए शिकारा, बच्चो के लिए किड्स जॉन सेल्फी बूथ और कश्मीरी फूड के लिए लाइव काउंटर बनाया गया हैं बच्चों के लिए किड्स जोन, सेल्फी बूथ व कश्मीरी फूड के लाइव काउंटर बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि डिनर में बुफे की व्यवस्था की गई हैं। जहां आकर मेहमान आनंद उठा सकते हैं। बेवरेज व अनलिमिटेड फूड के लिए भी ऑफर रखे गए हैं। प्रख्यात शेफ फारुख अहमदवानी ने बताया कि कश्मीरी फूड में लाइव काउंटर पर चिकन कण्टी, गाद मेथी टिक्का, तबक माज, रिसता, गुस्तबा, मेथी माज, स्टीम राइस, लवासा जैसे व्यंजन रखे गए हैं। वहीं मेन कोर्स में गोगजी मसाला और कश्मीरी राजमा और करम हाक और मूजी आत्यादि है। असिस्टेंट फूड एंड बेवरेज मैनेजर जितेंद्र सिंह के अनुसार, होटल में व्यंजनों के साथ संगीत का मजा भी लिया जा सकता है, इसके लिए हर एक दिन कोई न कोई कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। 24 दिसंबर को क्रिसमस के अवसर पे ग्रांड सेलिब्रेशन का आयोजन किया हैं जो क्रिसमस इन कश्मीर का नाम दिया गया हैं जिसमें इन कश्मीर, सूफी संगीत, मैजिक शो ,टैटू आर्टिस्ट जैसे कार्यक्रम होंगे।

पेड़ से लटकता मिला 16 वर्षीय किशोर का शव,पिता ने जताई हत्या की आशंका, गांव के दो लोगों पर लगा रहे आरोप

उरई/जालौन। जालौन में 16 वर्षीय किशोर का शव संदिग्ध परिस्थितियों में खेत में लगे बबूल के पेड़ पर तारों के फंदे से लटके मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी तब हुई जब खेत पर किसान अपनी फसल की रखवाली करने के लिए जा रहे थे, जहां उन्होंने बबूल के पेड़ पर किशोर के शव को लटका हुआ देखा, तत्काल पुलिस व ग्रामीणों को सूचना दी। सूचना मिलते ही कैलिया पुलिस फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंची, जिन्होंने किशोर के शव को नीचे उतारकर कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। मृतक के पिता ने हत्या की आशंका जताई साथ ही गांव के ही दो लोगों पर हत्या करने का आरोप लगाया, जिस पर पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी। घटना कैलिया थाना क्षेत्र के ग्राम गेंदोली है। यहां के रहने वाले दिनेश के 16 वर्षीय पुत्र निशांत का शव गांव के बाहर खेतों में लगे बबूल के पेड़ पर तारों से बने फंदे पर झूलता मिला, इस बारे में तब जानकारी हुई जब गेंदोली ग्राम के किसान अपने खेतों में काम करने जा रहे थे, जैसे ही उन्होंने बबूल के पेड़ पर निशांत के शव देख तत्काल उसके पिता दिनेश को सूचना दी, साथ ही पुलिस को अवगत कराया। गांव के बाहर खेत में शव मिलने से ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई, वहीं अपने 16 वर्षीय पुत्र के शव को देख पिता बेहोश हो गया, सूचना मिलते ही कैलिया थाना पुलिस के साथ कोंच सीओ उमेश कुमार पांडेय फॉरेंसिंक टीम के साथ मौके पर पहुंचे, जिन्होंने फॉरेंसिक टीम की मदद से मामले की जांच कराई, साथ ही शव को बबूल के पेड़ से नीचे उतरकर कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं मृतक के पिता दिनेश का आरोप है कि गांव के ही रहने वाले मनोज नाम के दो युवकों ने उसके बेटे की हत्या की है, मृतक के पिता दिनेश का कहना है कि शाम को मनोज और गांव अन्य लोग गांव में बदमाश–बदमाश कहकर चिल्ला रहे थे, उन्हे यह पता नहीं था उसके बेटे को ही बदमाश बताकर उसकी हत्या कर बबूल के पेड़ पर लटका देंगे। मृतक के पिता ने बताया कि बेटे को रात भर तलाश की, मगर उसका कहीं भी पता नहीं चला, आज उसका शव पेड़ पर लटका मिला। वही इस मामले में कोंच सीओ उमेश कुमार पांडेय का कहना है कि फॉरेंसिक टीम की मदद से मामले की जांच की जा रही है, साथ ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जिससे हत्या और आत्महत्या की सुलझा सके, उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।

नाबालिग से रेप करने वाले को 20 साल की सजा,

न्यायालय पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश ने सुनाई सजा

उरई/जालौन। जालौन में 5 साल पहले घर में घुसकर डरा धमकाकर नाबालिक से रेप करने वाले युवक को साक्ष्य और गवाहों के आधार पर बुधवार को न्यायालय पोक्सो एक्ट (मय रेप) के विशेष न्यायाधीश ने 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 30 हजार रुपये का आर्थिक दंड लगाया है, सजा सुनाई जाने के बाद पुलिस ने दोषी को तत्काल हिरासत में लेकर उरई जिला कारागार भेज दिया है। इस मामले की पैरवी करने वाले शासकीय अधिवक्ता बृजराज राजपूत ने बताया कि घटना 5 साल पुरानी डकोर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की हैं। उन्होंने अवगत कराते हुए बताया कि 12 मई 2018 को डकोर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 17 वर्षीय किशोरी अपने परिजनों के साथ सो रही थी, तभी रात्रि एक बजे गांव का रहने वाला रविंद्र पुत्र शंभू दयाल घर में घुस आया, जहां किशोरी का मुंह बंद कर उसे डरा धमकाकर घर में एकान्त में ले गया। जहां उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया और जान से मारने की धमकी देकर भाग गया। इस घटना की जानकारी किशोरी ने अपने परिवार के लोगों को बताई जहां सुबह जाकर उसने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई पुलिस ने रविंद्र के खिलाफ धारा 376 आईपीसी तथा 3/4 पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया, साथ ही पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजकर इस घटना को अंजाम देने वाले रविंद्र को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया। शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि पुलिस ने इस मामले में न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की, जिसका केस अदालत में 5 साल तक चला, जिसके बाद बुधवार को न्यायालय पोक्सो एक्ट (मय रेप) के विशेष न्यायाधीश मोहम्मद कमर एचजेएस द्वारा साक्ष्य और गवाहों के आधार पर रविंद्र को 20 साल कारावास की सजा सुनाई, साथ ही दोषी पर 30 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है। सजा सुनाई जाने के बाद दोषी को पुलिस ने हिरासत में लेकर उरई जिला कारागार भेज दिया।

अयोध्या शोध संस्थान का नाम बदलकर ''अन्तर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान अयोध्या'' रखने का निर्णय

संस्थान में होगा भगवान श्रीराम से जुड़े रामकथा साहित्य पर अध्ययन एवं शोध : जयवीर

भारत का वैदिक ज्ञान पूरी तरह वैज्ञानिक

लखनऊ। राज्य सरकार ने जनपद अयोध्या में संचालित अयोध्या शोध संस्थान को अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान करने के लिए इस संस्थान का नाम तत्काल प्रभाव से अन्तर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान अयोध्या करने का निर्णय लिया है। संस्कृति विभाग द्वारा संचालित अयोध्या शोध संस्थान 18 अगस्त 1986 से कार्य कर रहा है। रामायण का मूल आधार सनातन संस्कृति है, जिसकी जड़े वैदिक काल तथा उसके पूर्व से भी है। इसको दृष्टिगत रखते हुए वैदिक विज्ञान एवं साहित्य पर विस्तार से शोध करने की आवश्यकता है। इस परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार ने संस्थान का नाम बदलने का फैसला लिया है। प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि इसके नये नामकरण के संबंध में प्रमुख सचिव पर्यटन एवं संस्कृति तथा धर्मार्थ कार्य मुकेश मेश्राम की ओर से शासनादेश जारी करा दिया गया है। अन्तर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान परिवर्तित करने का उद्देश्य सम्पूर्ण विश्व में प्रभु श्रीराम से जुड़े रामकथा साहित्य पर गम्भीर अध्ययन एवं शोध कार्य करना है। सम्पूर्ण विश्व को एक सूत्र में पिरोने का एकमात्र तरीका सांस्कृतिक एकता है। इसलिए माध्यम से रामकथा एवं रामायण परम्परा से जुड़े विद्वानों एवं महापुरूषों के व्याख्यान व प्रवचन आदि से इस परम्परा को स्थाई बनाया जायेगा। अन्तर्राष्ट्रीय रामलीला मंचन से जुड़े हुए कलाकारों को एक दूसरे की

वैश्विक स्तर पर रामलीला के मंचन के दृष्टिगत सांस्कृतिक आदान प्रदान के क्रम में उन देशों की रामलीला का मंचन अयोध्या में तथा अयोध्या की सांस्कृतिक विरासत का प्रचार–प्रसार सम्पूर्ण विश्व में किया जायेगा। जयवीर सिंह ने बताया कि इस संस्थान के संस्कृति से परिचित होने तथा उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का मंच प्रदान किये जाने का कार्य किया जायेगा। इस प्रकार रामलीला मंचन से जुड़े लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जायेंगे। भारत का वैदिक ज्ञान पूरी तरह वैज्ञानिक है। समस्त वेदों में गणित, शिल्प विज्ञान, वायुयान विज्ञान, शल्य विज्ञान आदि का ज्ञान समाहित है। वैज्ञानिक युग के परिप्रेक्ष में वैदिक ज्ञान को डिजिटल फार्म में होना अत्यन्त आवश्यक है, ताकि जनसामान्य को आसानी से सुलभ कराया जा सके।पर्यटन मंत्री ने बताया कि विश्व के विभिन्न भाषाओं में रचित रामचरित पर आधारित ग्रन्थों, पुरातन परम्परा के वैदिक मंत्रों एवं इन पर लिखे गये विभिन्न टीकाओं पर और अधिक अनुसंधान किये जाने, विश्व की अनेक भाषाओं जैसे अंग्रेजी, फ्रेंच, रसियन आदि भाषाओं में उपलब्ध कराने के लिए यह संस्थान महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा। इसके साथ ही शोध कार्यों को जनमानस हेतु अधिक उपयोगी व व्यवहारिक बनाने का प्रयास करेगा। उन्होंने बताया कि देश एवं विदेश के विश्वविद्यालयों में शोधरत छात्रों को संस्थान से जोड़ने के लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों को संस्थान से सम्बद्ध कराया जायेगा। संस्थान द्वारा शोध साहित्य का कम से कम कीमत पर आमजनता को सुलभ कराया जायेगा।

पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह आज से गोरखपुर वाराणसी व सोनभद्र दौरे पर

लखनऊ। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री एवं प्रभारी मंत्री वाराणसी जयवीर सिंह 15 दिसम्बर से 18 दिसम्बर तक वाराणसी, गोरखपुर तथा सोनभद्र के भ्रमण पर रहेंगे। पर्यटन मंत्री कल गोरखपुर में होटल कोर्टयार्ड बाई मैरियट के शुभारम्भ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ शामिल होंगे। अगले दिन 16 दिसम्बर को हिन्दुवारी के पास ग्राम गेंगुआर, रॉबर्टगंज सोनभद्र में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में शामिल होंगे। मऊ कलाग्राम तहसील सदर रॉबर्टसगंज सोनभद्र में पर्यटन विभाग की भूमि पर प्रस्तावित टेन्ट सिटी का निरीक्षण करेंगे। इसके उपरान्त धंधरौल डैम, तहसील सदर रॉबर्टगंज को पर्यटन के उद्देश्य से विकसित करने के लिए निरीक्षण करेंगे। इसके उपरान्त सलखन फासिल्स पार्क का भ्रमण करेंगे। शाम को सोनभद्र में अबारी पिकनिक स्पॉट ओबरा का निरीक्षण करेंगे। इसके उपरान्त हाथी नाला बायोडावर्सिटी हॉट स्पॉट के भी निरीक्षण का कार्यक्रम है। भ्रमण यात्रा के अंतिम चरण में अगले दिन रविवार को वाराणसी में प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों में शामिल होंगे और 18 दिसम्बर को दोपहर तक लखनऊ वापस आयेंगे।

80-करोड़ की लागत से बनी योजनाओं का लोकार्पण,

जतिन प्रसाद बोले, बीजेपी की सरकार घोषणा नहीं करती, काम करके दिखाती है

बहराइच। यूपी के लोक निर्माण मंत्री जतिन प्रसाद गुरुवार को एक दिवसीय दौरे पर बहराइच पहुंचे। कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र में तकरीबन 80 करोड़ की लागत से निर्मित योजनाओं एवं टेढ़ी नदी पर 14 करोड़ की लागत से बनाए गए एक पुल का भी लोकार्पण किया। योजनाओं के लोकार्पण करने के बाद लोक निर्माण मंत्री जतिन प्रसाद ने कहा कि बीजेपी की सरकार घोषणा नहीं करती, बल्कि काम करके दिखाती है। बीजेपी की सरकार में जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम जारी है। जतिन प्रसाद ने विपक्ष पर वार करते हुए कहा कि पहले की सरकारों में केवल वादे

हुआ करते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी एवं योगी के नेतृत्व में विकास की गतिमान धारा बहाने का प्रयास करती है। डबल इंजन की सरकार शहर के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों का कायाकल्प कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा जो कहती है वो कर दिखाती हैं। उसका ही परिणाम है कि दूर दराज इलाकों में इतने वर्षों में कुछ नहीं हुआ। वहां भाजपा सरकार सड़कों का जाल बिछा रही हैं। इससे गांव के विकास के साथ रोजगार के भी साधन बढ़ेंगे।

दिव्यांग को वाहन ने कुचला, मौत,

बस्ती। बस्ती के हर्रैया कोतवाली क्षेत्र के बबुरहवा के पास हाईवे पर एक दिव्यांग को अज्ञात वाहन ने कुचल दिया, जिससे उसकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई। दिव्यांग का शव इस कदर छत–विछत हो गया था कि शव को पुलिस ने टुकड़ों में इकट्ठा किया। उक्त थाना क्षेत्र के कुचेला गांव निवासी दिव्यांग सुजीत द्विवेदी 28 घर से ट्राई साईकिल से हर्रैया के लिए किसी काम से निकले थे, अभी वे बबुरहवा के पास पहुंचे ही थे कि अज्ञात वाहन ने उन्हें कुचल दिया, जिससे घटना स्थल पर ही उनकी दर्दनाक मौत हो गई। दुर्घटना के बाद हाईवे पर दिव्यांग सुजीत का शव पड़ा रहा, और यहां से गुजरने वाली तेज रफ्तार गाड़ियां शव को रौंदते हुए आ जा रही थी, जिसके चलते सुजीत का शव पूरी तरह से छत विछत हो गया था, मौके पर पहुंचे पुलिस कर्मियों ने किसी तरह शव के टुकड़ों के इकट्ठा किया और पंचनामा कराकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस सूत्रों के अनुसार मृतक का शव इस कदर छत बिछत हो गया था कि उसकी पहचान कर पाना आसान नहीं था, लेकिन मृतक के पास मौजूद पहचान के पत्र के आधार पर उसकी पहचान कुचेला गांव निवासी सुजीत द्विवेदी के रूप में हुई। मृतक के भाई अजीत द्विवेदी ने बताया सुजीत उनके बड़े भाई थे और वह 80 प्रतिशत दिव्यांग थे, बताते हैं कि इसके बावजूद भी वह घर के कामों में हाथ बंटाया करते थे, बताते हैं कि एक बहन भी है, जो सबसे बड़ी है, जिसका विवाह हो चुका है। दूसरे नंबर पर सुजीत थे। इस संबंध में हर्रैया कोतवाल राना डीपी सिंह ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी, मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, मामले में विधिक कार्रवाई की जा रही है।

संदिग्ध हालत में महिला ने लगाई फांसी,आर्थिक तंगी बताया जा रहा कारण, पुलिस जांच में जुटी

उरई/जालौन। जालौन में आर्थिक तंगी से जूझ रहे एक मजदूर की पत्नी ने परेशान होकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना से घर में कोहराम मच गया। जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची, और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, साथ ही मामले की जांच शुरू कर दी। मामला कोंच कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम गोरा की है। यहां का रहने वाला अनिल अहिरवार मजदूरी करके परिवार का भरण पोषण कर रहा था, मगर काम ज्यादा न मिलने के कारण वह अपने परिवार का भरण पोषण सही नहीं कर पा रहा था। वह में मजदूरी करने मंगलवार को गया था, जो देर रात को वापस नहीं लौटा। जबकि घर पर उसकी पत्नी राजकुमारी दो बच्चों के साथ उसका इंतजार कर रही थी। रात तक घर न लौटने पर देर रात को अनिल की पत्नी राजकुमारी ने संदिग्ध हालत में बच्चों को सुलाकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सुबह बच्चों ने जब मां को फांसी के फंदे पर लटका देखा, तो रोते बिलखते पड़ोसी के घर पहुंचे, बच्चों को रोता देख पड़ोसी उसके घर आए, जहां राजकुमारी को फंदे पर लटका हुआ देखा इसकी सूचना पुलिस को दी गई। जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। वहीं मृतका के भाई कृष्ण कुमार निवासी ग्राम सदुपुरा ने बताया कि परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा था, इसके जीजा अनिल काम करने बाहर जाता था, मगर उसको काम न मिलने से परेशान था और परिवार का भरण पोषण सही नहीं कर पा रहा था, इसी परेशानी से बहिन ने फांसी लगाई। वही पुलिस मामले की जांच में जुटी साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतेजार कर रही है।

अवध की आवाज हिन्दी दैनिक, प्रकाशक ,मुद्रक व स्वामी,अनिल कुमार सिंह द्वारा स्काई लाइन प्रिन्टर्स,119/23 खन्दारी लेन, लालबाग, लखनऊ उ0प्र0 से मुद्रित तथा डी–97/3 व 7,सेक्टर–7, इन्दिरा नगर,लखनऊ,उ0प्र0 से प्रकाशित। सम्पादक अनिल कुमार सिंह फोन : 0522–4340954 मो0–7905407289, Email: avadhkiaawaz@gmail.com
R.N.I.-UPHIN/2012/45127
नोट : समाचार पत्र से सम्बंधित सारे विवादोंका न्याय क्षेत्र लखनऊ होगा।